Registration No. RAJBIL /2016 / 69093
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

लघु उद्योग भारती

UDYOG TIMES

Volume - 09 Issue - 07 May - 2026
Total Pages - Price - Rs. 100

पूरब के विकास का नव ग्रोथ सेंटर
पश्चिम बंगाल

कर्मयोगी

के. के. सेकसरिया
सफल उद्यमी एवं समाजसेवी
कोलकाता

aZesty | PARROT | KLWI

Since 1984

Financially Strong Distributors Required

Contact for Business Enquiry

7360011401

mail:parrotmasala1@gmail.com

UDYOG TIMES

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

Volume -9 Issue - 7 May 2026

Editorial Board

■ *Patron*

Shri Madhusudan Dadu, National President	098102-56494
Shri Prakash Chandra ji, National Org. Secretary	099299-93660
Shri Om Prakash Gupta, National Gen. Secretary	095602-55055

■ *Editor*

Dr. Kirti Kumar Jain	094141-90383

■ *Co-Editor*

Dr. Sanjay Mishra	098295-58069

विवरणिका

Editorial	03
पश्चिम बंगाल -पूरब का ग्रोथ कंेद्र	05
अर्थायाम का भारतीय दर्शन	09
Karmyogi - K.K.Seksaria	12
Plastic Waste Management Rules	15
Innovation: Easy, Effective & Economical	19
Business Ecosystem in Karnataka	21
झारखंड में लघु उद्योगों से स्वदेशी उत्पादन	25
Industry-Academia	26
पाली में बिखरेगा कौशल का 'प्रकाश'	28
उत्पाद समूह चिंतन-बैठक	31
मिशन ज़ीरो टोलरेंस	32
LUB's News in Brief	33

Annual Membership: Rs. 1200 Including Postage

Corporate & Head Office :
Shri Vishwakarma Bhawan 48, Deen Dayal Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002
Website : www.lubindia.com
Email : headoffice@lubindia.com
Ph.: 011-23238582

Registered Office :
Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011
Ph.: 0712-2533552

India Achieved Robust 7.7 pc GDP Growth in 2025-26

Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain
kkjain383@gmail.com

India's GDP growth was estimated at a robust 7.8 per cent in the January-March quarter (Q4) of 2025-26, as result of which the growth rate for the full financial year works out to 7.7 per cent on the back of a strong performance of the agriculture, construction, and service sectors. The secondary sector recorded a strong 8.8 per cent growth while the tertiary sector grew by 9.9 per cent, according to the official statement.

The primary sector recorded a 3.2 per cent growth, mainly driven by the performance of the agriculture and fisheries sectors.

Manufacturing, trade, repair, hotels, transport, communications and services related to broadcasting, storage, financial, real estate, and professional services sectors have attained double-digit growth during 2025-26, the official statement said.

On the expenditure side, both private and final consumption expenditure and gross fixed capital formation have exhibited over 7.5 per cent growth during 2025-26.

This reflects the massive investments by the government in big infrastructure projects, such as highways, railways, ports and airports, which have helped to drive up the growth rate.

India continues to be the fastest-growing economy amid the global slowdown. The IMF had forecast India to be the only economy that is expected to clock an over 6 per cent growth rate in 2025-26 as the US tariff turmoil was expected to disrupt world trade and slow down the growth of the global economy.

❑❑❑

Laghu Udyog Bharati-Karnataka

Belgaum Ferrocast (India) Pvt. Ltd.

www.bfplindia.com

DUCTILE & GREY IRON CASTINGS

CASTINGS | MACHINING | ASSEMBLIES | EXPORT

Corporate Office & Machine Shop Unit I :
Plot No. 7A & 8A, R.S No. 680/2, BEMCIEL, Udyambag, Belgaum-590 008. Karnataka, India.
Tel. : + 91 831 2440665, 2441185 Fax : + 91 831 2441185 E-mail : bfplindia@bfplindia.com

Foundry Unit II :
Plot No. 150, Sy No. 585 & 589, BEMCIEL Indl. Estate, Machhe, Belgaum – 14.
Tel. : +91 831 2411319, 2411052 E mail: foundry@bfplindia.com

Foundry Unit III :
Plot No. 11 & 20, BEMCIEL Indl. Estate, Machhe, Belgaum – 14.
Tel. : +91 831 2411319, 2411052 E mail: foundry@bfplindia.com

For Enquiry : +91 948 083 9955
E-mail : export@bfplindia.com

Niranjan Sant
Executive Chairman
+91 984 526 1612
E-mail : niranjansant@bfplindia.com

Dr. Sachin Sabnis
Managing Director
+91 984 527 3756
E-mail : sachinsabnis@bfplindia.com

RiGAS
LPG Management System

RiGas is the smart LPG management system, which monitors the LPG level in the Gas cylinder and communicates the level to the mobile application. The refill LPG cylinder can be booked through the Mobile App once Gas reaches low level.

The most important aspect of the RiGas is that "the Gas leak safety alert system" through the mobile app for the Gas leak.

RiMASS
Solutions for Weight Measurement

RiMass is the weighing machines manufacture by us. We have the weighing machines ranges from 50 Kg. to 5000 Kg. It is manufactured with Bench type economic scales and superior platform ranges. We manufacture the weighing machines as per custom requirements for industrial, chemical, agricultural, poultry, dairy, warehouse and general requirements.

SUPRAM

Unit I: # 34, Sir M. Vishweshwaraiah Indl. Layout, Alahalli, Anjanapura Post, Bengaluru - 560 018. INDIA **Mobile: +91 98455 08278 | 80500 27459**
Unit II: # 3, Sy. No. 179/2, Chandrani Industrial Estate, Anjanapura Main Road, Glass Factory Circle, Kothanur, Bangalore - 560 062
Email: sales@supramindustries.com | info@supramindustries.com
www.supramindustries.com | www.rigas.in

Follow us:

ACCUTECH ENTERPRISES

AS 9100D & ISO 9001:2015 Certified Company

•Precision CNC Machining
• Precision Sheet Metal Works

Works: #480/A2, 1st Cross, 3rd Stage, PIA, Bengaluru-560058
Contact Point: Pavith U, +91 7892003161
Mail: contact@accutechenterprises.com
Website: www.accutechenterprises.com

CEEPEETECH FAB INDIA PVT. LTD

AN ISO 9001:2015 Certified Company
Manufacture of : Precast Casting Cells, Lauching Gantry's Form Travellers, Cable Stay Bridge Equipments and All types of Anchor Heads

N.C. Dhanya Kumar
Managing Director
M: +91 9886063604
ceepeetech_dhanya@yahoo.com
dhanya@ceepeetech.com
www.ceepeetech.com

PARAM MACHINES AND MOULDS

No.68, Tanisha, 11th Main, 19th Cross, T.G Layout, Banshankari 3rd Stage, Bangalore - 560 085
Mobile: +91 9740814471 | +919900760083
E-mail: parammachines@gmail.com | ravirsg@gmail.com **Website:** www.parammachines.com

पश्चिम बंगाल बन सकता है पूरब का ग्रोथ केंद्र

सामयिक
डॉ. अश्वनी महाजन
जाने–माने आर्थिक विश्लेषक
राष्ट्रीय सह–संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच
पूर्व प्रोफ़ेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय
ashwanimahajan@rediffmail.com

हाल ही के चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने दो तिहाई से ज्यादा जनमत प्राप्त कर सरकार का गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे देश में यह आशा बलवती हुई है कि पश्चिम बंगाल पुनः अपने ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त कर विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा।

वर्ष 2024–25 में चालू कीमतों पर पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय 1.63 लाख रुपये थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत 2.05 लाख रुपये था। इस प्रकार, वर्ष 2024–25 में पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का लगभग 79.5 प्रतिशत रही, और राष्ट्रीय स्तर पर सालाना प्रति व्यक्ति आय और पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय में 42,000 रुपये का अंतर रहा।

लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं रही। वर्ष 1960–61 में पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय औसत का 127.5 प्रतिशत थी। 1970–71 में भी वो राष्ट्रीय औसत से 18 प्रतिशत अधिक थी। लेकिन 1980–81 तक आते–आते उसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 97 प्रतिशत और 2010–11 तक मात्र 84 से 86 प्रतिशत रह गई थी, और यह प्रवृत्ति अभी तक जारी है।

1970 के दशक में जहां भारत की जीडीपी 3.0 से 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही थी, पश्चिम बंगाल की जीडीपी वृद्धि दर सिर्फ 1.5 से 2.0 प्रतिशत ही थी। 1980 के दशक में

Haldia Industrial Park

Tajpur Deep Sea Port

हालांकि पश्चिम बंगाल में जीडीपी ग्रोथ 5.5 प्रतिशत तक पहुंच गई, लेकिन औद्योगिक विकास की गति अत्यंत धीमी रही। 1990 के दशक में पश्चिम बंगाल की वृद्धि दर राष्ट्रीय संवृद्धि दर से अधिक थी। 2000 से लेकर 2011 के बीच हालांकि औद्योगिक उठाव तो नहीं आया, लेकिन सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण पश्चिम बंगाल ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। 2011 और 2025 के बीच भी पश्चिम बंगाल की ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से कम थी, और यह 6.5 से 7.0 प्रतिशत रही।

चूंकि पश्चिम बंगाल देश के अन्य हिस्सों से कम गति से विकास कर रहा था, देश की कुल जीडीपी में इसका हिस्सा 1960 में 10.5 प्रतिशत से घटता हुआ वर्ष 2024–25 में मात्र 5.6 प्रतिशत रह गया। इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में सेवा क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन, व्यापार, ट्रांसपोर्ट और सरकारी खर्च की बदौलत जीडीपी में वृद्धि तो हुई, लेकिन गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कई नए औद्योगिक प्रदेशों की तुलना में पश्चिम बंगाल का औद्योगिक विकास अत्यंत धीमा रहा।

गौरतलब है कि 1970 और 1990 के बीच में पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा नुकसान औद्योगिक गिरावट के कारण हुआ, जिसके चलते पश्चिम बंगाल का हिस्सा भारत की जीडीपी में नीचे गिर गया। उसके उपरांत पश्चिम बंगाल में जीडीपी ग्रोथ पहले से बेहतर होने के बावजूद भी, पश्चिम बंगाल का हिस्सा राष्ट्रीय जीडीपी में कम बना रहा। प्रश्न यह है कि क्या पश्चिम बंगाल पुनः अपना वह गौरव प्राप्त कर पाएगा? क्या एक समय का औद्योगिक राज्य, जहां अन्यान्य कारणों से उद्योग विमुख हो गए, पुनः उद्योगों की स्थापना कर पाएगा? क्या पश्चिम बंगाल की प्रतिव्यक्ति आय जो आज राष्ट्रीय औसत का मात्र 79.5 प्रतिशत ही है, पुनः राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे ज्यादा हो पाएगी? ये सभी यक्ष प्रश्न देश के सामने हैं और भाजपा की नवगठित सरकार के सामने यह चुनौती भी प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि एक राज्य जो पूर्व में आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्यों में से एक था, जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 27 प्रतिशत से भी ज्यादा बेहतर थी, उसे वापिस पटरी पर कैसे लाया जाए। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की आर्थिक बदहाली के कारणों की जांच करनी होगी और उनके समाधान का खाका तैयार करना होगा। यह भी स्पष्ट है कि जब आर्थिक गिरावट आती है, तो न तो एक कारण होता है और न ही एक समाधान।

सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की आर्थिक बदहाली का कारण वहां औद्योगिक क्षेत्र के विकास में व्यवधान रहा। औद्योगिक विकास हेतु सर्वप्रथम इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जरूरी होता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पश्चिम बंगाल काफी पिछड़ गया। सड़क, बिजली आदि का तो अभाव रहा ही, साथ ही औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन भी न्यूनतम रहा। गौरतलब है कि पूर्व में साम्यवादी शासन में निवेश घटा और निवेशक हड़ताल और श्रम विवादों के चलते पश्चिम बंगाल से विमुख हो गए। जब पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने टाटा को सिंगूर में नैनो कार प्लांट लगाने की इजाज़त देकर पिछली गलतियों को सुधारने की कोशिश की, तो इस बार विपक्ष की नेता ममता बनर्जी ने टाटा को ज़मीन देने के खिलाफ़ आंदोलन कर दिया, जिसके

कारण वो प्रस्तावित कारखाना टाटा ने गुजरात स्थानांतरित कर दिया। हालांकि यह विवाद तो मीडिया की चर्चा में रहा, लेकिन पिछले 60–70 सालों में ऐसे कई अवसर आए, जिसके कारण उद्योग पश्चिम बंगाल से विमुख होते गए। बिरला, टाटा समेत कई उद्योग समूहों ने अपना मुख्यालय कोलकाता से अन्य स्थानों की ओर स्थानांतरित कर दिया। श्रम विवादों के राजनीतिकरण और आधुनिकीकरण और ऑटोमेशन की खिलाफत ने राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है।

ऐसे में यह समझना होगा कि पश्चिम बंगाल अपने भूगोल, मानव संसाधनों एवं सांस्कृतिक और औद्योगिक परंपराओं के चलते औद्योगिकीकरण के लिए अत्यंत उपयुक्त राज्य है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी देन है, जो आसियान देशों के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यापार का प्रमुख द्वार बन सकता है। कृषि की उच्च उत्पादकता, कोलकाता जैसा शहर और उस पर पढ़ी–लिखी जनसंख्या पश्चिमी बंगाल को ग्रोथ हब बना सकता है। यदि शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बने और मैट्रो कनैक्टिविटी हो सके, तो कोलकाता को एक आईटी हब के नाते विकसित किया जा सकता है। उच्च कोटि और अधिक उत्पादकता वाली कृषि के चलते यहां बागवानी, मछली पालन और फूलों के उत्पादन की संभावनाएं हैं ही, और साथ ही साथ यदि वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगें, और कोल्ड चेन को मजबूत किया जाए और निर्यात को बढ़ावा मिले, तो ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी को बढ़ाने में एक बड़ी छलांग लग सकती है।

कौशल विकास और श्रम सुधार पश्चिम बंगाल के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। हमें वहां औद्योगिक संबंधों के लिए वातावरण को बेहतर करना होगा और साथ ही महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को भी बढ़ाना होगा।

साम्यवादी शासन के दौरान शासक वर्ग की विचारधारा का बड़ी कंपनियों के प्रति संशय का भाव, नियामक वातावरण और विकास से पहले ही पुनर्वितरण के प्रयासों ने विकास को नुकसान पहुंचाया। परंपरागत उद्योगों के ह्रास ने भी पश्चिम बंगाल के विकास को बाधित किया, खासतौर पर तब जब नए उद्योगों का प्रादुर्भाव वहां नहीं हो पाया। सरकार बदलने के बाद आज परिस्थिति बदली है और आशा की जा सकती है कि भाजपा की स्थाई सरकार बनने के बाद निवेशक पश्चिम बंगाल की तरफ आकर्षित होंगे।

1991 के बाद अनुकूल वातावरण के कारण अन्य राज्यों को विदेशी और घरेलू निवेश प्राप्त हुआ। इन राज्यों ने आईटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया। लेकिन पश्चिम बंगाल इस प्रकार के निवेश को आकर्षित नहीं कर पाया और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने भी इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता नहीं दी। सरकार को विभिन्न प्रकार के अनुपादक खर्चों को कम करते हुए पूंजीगत खर्च को बढ़ाना होगा, प्रशासन में डिजीटलीकरण बढ़ाकर सरकारी धन के रिसाव को कम करना होगा।

पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों और सुंदरवन के प्राकृतिक टूरिज्म को तो बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ ही पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को वैश्विक सांस्कृतिक ब्रांड के रूप में भी विकसित किया जा सकता है।

देश का पूर्वी हिस्सा खनन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए तो जाना ही जाता है, उत्तर–पूर्व के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करते हुए उड़ीसा और झारखंड के संसाधनों के साथ समन्वय बैठाते हुए पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत की आर्थिक संवृद्धि का केन्द्र बन सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ विमर्शों को बदलते हुए एक औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए यदि विकास का मॉडल तैयार हो, और लोगों में एक विश्वास बने, तो पश्चिम बंगाल अपने पूर्व के वैभव को पुनः प्राप्त करने में सफल हो सकता है।

❑ ❑ ❑

With Best Compliments from- LUB's Jammu & Kashmir State Unit

BHARAT
STERILE PVT. LTD.
(Manufacturer of Sterile API)

BHARAT STERILE PRIVATE LIMITED
API STERILE MANUFACTURING UNIT

Purity in every process, Quality in every product.

OUR PRODUCT RANGE (STERILE APIs)

- Ceftriaxone Sodium Sterile
- Cefuroxime Sodium
- Sulbactam Sodium
- Meropenem for Injection
- Pantoprazole Sodium
- Omeprazole Sodium
- Artesunate
- Ampicillin Sodium Sterile
- Amoxicillin Sodium Sterile
- Amox-Clav (Amoxicillin + Clavulanate)
- Avibactam

- State-of-the-Art Manufacturing Facility
- Stringent Quality Control
- Experienced & Dedicated Team
- Commitment to Health & Safety

Our Commitment, Your Confidence

At Bharat Sterile Private Limited, we are dedicated to delivering high-quality sterile APIs through advanced technology, stringent processes, and a commitment to excellence.

ASSURED QUALITY | ADVANCED TECHNOLOGY | TIMELY DELIVERY | GLOBAL QUALITY, TRUSTED PARTNER

23A, 23B, 28A & 28B, SICOP, Kathua, Jammu & Kashmir 184102

QUALITY YOU CAN TRUST.
PARTNER YOU CAN RELY ON.

www.bharatsterile.com | info@bharatsterile.com

AGRO TECH AROMATICS PVT. LTD.
WE ANALYZE, YOU TRUST.

We Analyze, You Trust.

A Complete Testing House – Food, Drug and Environment
First Testing Lab in J&K

UNITED ACCREDITATION FOUNDATION UAF
CPCB
CERTIFIED ISO 14001 COMPANY
CERTIFIED ISO 45001:2018 COMPANY
CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

SIDCO Industrial Complex, EPIP, Kartholi, Bari Brahmana-181133 J&K;
Phone: 9872923100

अर्थायाम का भारतीय दर्शन

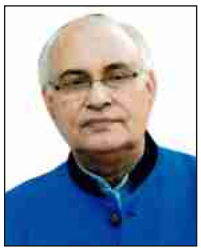

मंथन
डॉ. महेश चंद्र शर्मा
प्रख्यात चिंतक एवं अध्यक्ष,
एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान एवं
विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
mahesh.chandra.sharma@live.com

एकात्म मानव के लक्ष्यभूत कार्य को दीनदयाल उपाध्याय चतुर्आयामी मानते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में इन आयामों को चतुर्पुरुषार्थ कहा जाता है, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। अतः एकात्म मानवदर्शन का महत्वपूर्ण विचार है, चतुर्पुरुषार्थ। इन पुरुषार्थों को विविधायामों में पं. दीनदयाल उपाध्याय ने विवेचित किया है। 'अर्थायाम' को हमें उन्हीं के माध्यम से जानने का प्रयत्न करना चाहिए।

पं. दीनदयाल उपाध्याय के सम्पूर्ण सार्वजनिक कार्यों का मंच भारतीय जनसंघ था। अतः वे जनसंघ के संदर्भ में ही अपने विचारों का स्पष्टीकरण देते हैं। समग्रतावादी दार्शनिक होने के कारण पं0 दीनदयाल उपाध्याय उन लोगों से हर विषय पर असहमत रहते हैं, जो जीवन के किसी विशिष्ट आयाम को जीवन की समग्रता का नियामक मान बैठते हैं अथवा एक ही पहलू की ऐसी अतिरेकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जिसमें जीवन के अन्य विविध पहलुओं की उपेक्षा हो जाती है। इस संदर्भ में उपाध्याय लिखते हैं:

भारतीय जनसंघ के पास एक स्पष्ट आर्थिक कार्यक्रम है; किन्तु उसका स्थान हमारे सम्पूर्ण कार्यक्रम में उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में अर्थ का। पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवादी होने के कारण अर्थप्रधान है। हम भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों का समन्वय करना चाहते हैं। अतः यह निश्चित है कि जनसंघ उन अर्थशास्त्रियों व दलों से, जो अर्थ के सामने जीवन के प्रत्येक मूल्य की उपेक्षा करके चलना चाहते हैं, इस मामले में सदैव पीछे रहेगा।

जनसंघ हृदय, मस्तिष्क और शरीर तीनों का सम्मिलित विचार करता है। इसी कारण कुछ लोग जनसंघ पर यह

आरोप लगाते हैं कि जनसंघ आध्यात्मिकता की उपेक्षा करता है, महर्षि अरविंद आदि महापुरुषों की भाषा नहीं बोल पाता। हम दोनों ही प्रकार के आरोपों का स्वागत करते हैं और इतना ही कहना चाहते हैं कि अर्थ, समाज की धारणा के लिए आवश्यक है। जितने मात्र से व्यक्ति अपना भरण–पोषण करके अन्य श्रेष्ठ मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सके, उतने को ही हमने अपने कार्यक्रम में स्थान दिया है।''

अपने आर्थिक चिन्तन को व्याख्यायित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ने 'भारतीय अर्थनीतिः विकास की एक दिशा' नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक में अर्थनीति की विवेचना करते हुए उन्होंने अपने 'एकात्म मानव' के अर्थायाम की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। "समाज से अर्थ के प्रभाव व अभाव दोनों को मिटाकर उसकी समुचित व्यवस्था करने को 'अर्थायाम' कहा गया है।''

1. भारतीय संस्कृति में अर्थ

भारतीय संस्कृति में 'धर्म' को आधारभूत पुरुषार्थ माना गया है। 'सुखस्य मूलम् धर्मः। धर्मस्य मूलमर्थः।' चाणक्य के इस कथन के अनुसार 'अर्थ के बिना धर्म नहीं टिकता। 1953 में लिखे अपने प्रथम अर्थनीति प्रलेख में उपाध्याय लिखते हैं:

'.... हम जानते हैं कि भारतीय ढंग सदा से ही धर्म का ढंग रहा है (मजहब का नहीं) और धर्म के इस ढंग पर ही आर्थिक नवनिर्माण के लिए नक्शे को तैयार करने की जरूरत है। धर्म की वेदों की व्याख्या हम लेते हैं जिसमें उसके 12 लक्षण

गिनाए गए हैं। इनमें धर्म का आद्यलक्षण सबसे महत्त्वपूर्ण है (श्रमेण तपसा सृष्टा ...) और वह है 'श्रम'। 'श्रम' को धर्म का पहला लक्षण बताया। श्रम की महत्ता का ज्ञान मार्क्स और एंजिल्स के जन्म तक रुका नहीं रहा। वह अति पुरातनकाल में सहज अनुभूति से हमने मानवता को दे दिया था। श्रम करना मनुष्य का मूलभूत कर्तव्य (Duty to work) है। इसी प्रकार मनुष्य को श्रम करने का यह अधिकार देना राज्य का मूलभूत कर्तव्य है। ..... अतः श्रम का अधिकार (Right to work) मनुष्य का संवैधानिक अधिकार है। राज्य का यह पहला कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर दे। इन अवसरों में किसी प्रकार का भेदभाव, न जाति का, न रंग का और न लिंग का होने दें। राष्ट्र के पुनर्निर्माण की जो भी योजना बनाई जाए, उसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों को काम (Full employment) दिलाना होना चाहिए।' इसी आधार पर दीनदयाल उपाध्याय पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के संदर्भ में सदैव यह आग्रह करते रहे कि हमें अपना आयोजना–लक्ष्य घोषित करना चाहिए 'सब को काम'।

2. धन का मनोविज्ञान

धन का अभाव मनुष्य को चोर बनाता है। अभाव के क्षणों में की गई चोरी को भारतीय शास्त्रकार अपराध नहीं वरन् 'आपद्धर्म' की संज्ञा देते हैं। "उन्होंने (विश्वामित्र ने) धर्म की अनेक मर्यादाओं को भंग किया। आपद्धर्म की संज्ञा देकर शास्त्रकारों ने उनके इस व्यवहार को उचित ठहराया है। यदि अर्थ के अभाव की आपत्ति बनी रहे, तो फिर आपद्धर्म अर्थात् चोरी ही धर्म बन जायेगा। यदि यह आपत्ति समष्टिगत हो जाये अथवा समष्टि का बहुतांश इससे व्याप्त हो जाये, तो वे एक–दूसरे की चोरी करके अपने आपद्धर्म का निर्वाह करेंगे।'

अर्थात् समाज में अर्थ का अभाव अथवा अभावमूलक नियोजन समाज में अधर्म को धर्म बना देता है। वैसे ही अर्थ का प्रभाव भी धर्म का नाश करता है। .....अर्थ जब अपने में या उसके द्वारा प्राप्त पदार्थों में और उससे प्राप्त भोग–विलास में संग (आसक्ति) उत्पन्न कर देता है, तब अर्थ का प्रभाव कहा जाता है। 'सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति'..... जब समाज में सभी 'धनपरायण' हो जाएँ, तो प्रत्येक कार्य के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता होगी। धन का यह प्रभाव प्रत्येक के जीवन में अर्थ का अभाव उत्पन्न कर देगा।'

इसलिए वे यह प्रतिपादित करते हैं कि "समाज के मानदण्ड ऐसे बनाए जायें कि हर वस्तु पैसे से न खरीदी जा सके।..... पैसे से ही मूल्य आँकने का परिणाम यह होगा कि दुर्बल की रक्षा ही नहीं हो पायेगी। शरीर शक्ति में दुर्बल अपनी बुद्धि का उपयोग कर धूर्तता से धन कमाकर अपनी रक्षा का मूल्य चुकायेगा (घूसखोरी होगी)। श्रम का रुपये पैसे में मूल्य आँकना असंभव है।

..... श्रम और पारिश्रमिक दोनों का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में धनिष्ठ सम्बन्ध होने पर भी व्यवहारजगत् के लिए सर्वमान्य एवं सर्वकष मूल्य सिद्धांत निश्चित करना न तो सरल है और न उपादेय ही। वास्तविकता तो यह है कि दोनों का मूल्यांकन पृथक मानदण्ड से होता है। श्रम की प्रतिष्ठा उससे मिलने वाले अर्थ के कारण नहीं, अपितु उसके धर्मत्व से है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को दिया गया पारिश्रमिक उसके द्वारा किए श्रम का प्रतिदान नहीं वरन् उसके 'योगक्षेम' की व्यवस्था है।'

उपाध्याय इस प्रकार के समाजशास्त्र व मनोविज्ञान के हिमायती हैं जिसमें कर्म की प्रेरणा का आधार लोभवृत्ति नहीं वरन् 'कर्तव्यसुख' है। वे उस अर्थशास्त्र के खिलाफ हैं जो मानवजीवन के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा करता है।

'..... व्यक्तियों की अबाध व असीम प्रतिस्पर्धा को न तो हम सामाजिक जीवन का नियामक मान सकते हैं और न सुरक्षापूर्ण ही। यह मान्यता मात्स्य न्याय का प्रतिपादन करने वाली है। हमने इस न्याय को कभी धर्मसंगत नहीं माना।.... समाज में मानव की कुछ स्वतंत्रताओं पर मर्यादा आवश्यक होती है। अनियंत्रित स्वतंत्रता केवल कल्पना की वस्तु है। हाँ, यह नियंत्रण जितना बाहरी होगा, मानव को कष्टदायी होगा। शिक्षा और संस्कार, दर्शन और आदर्शवाद, व्यवहार में मनुष्य को आत्मनियंत्रण सिखाते हैं।'

अपनी ही गति से चलनेवाले अर्थशास्त्र के हवाले समाज को

नहीं किया जा सकता। अर्थचक्र को समाजशास्त्र व धर्मशास्त्र के अनुकूल नियोजित करना आवश्यक है। इसलिए वे कहते हैं, "अपनी ही गति से बराबर गतिमान् अर्थव्यवस्था असंभव है। उसे गति देने के लिए और बाद में भी कम–से–कम रुकावट के साथ सुचारु रूप से चलते रहने के लिए, व्यक्ति और समाज के जीवन में प्रेरणा का स्रोत अर्थ के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र ढूँढ़ना होगा। राष्ट्र की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएँ, व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा की अभिलाषा, कुटुम्ब का प्रेम आदि अनेक प्रेरणाएँ वांछित अर्थरचना को बनाने व टिकाने में सहायक होती है।'

उपाध्याय की मान्यता है कि उपभोगवाद, स्पर्धावाद व वर्गसंघर्ष इन सबका आधार अनियंत्रित उपभोग है। "पश्चिम ने अधिकाधिक उपभोग के अपने पुराने सिद्धांत को ही चलने दिया और उसमें संशोधन की जरूरत नहीं समझी। वास्तविकता यह है कि अधिकाधिक उपभोग का सिद्धांत ही मनुष्य के दुःखों का कारण है। उपभोग की लालसा यदि पूरी की जाय, तो यह बढ़ती चली जाती है।

वर्गसंघर्ष, जिसके ऊपर समूचा साम्यवाद खड़ा है, ऐसे उपभोग के कारण ही उत्पन्न होता है। भारतीय मतवाद जब वर्गसंघर्ष का खण्डन करता है, तब उसका तात्पर्य यही होता है कि उसने उपभोग को नियंत्रित कर लिया है तथा अधिकाधिक उपभोग की बजाय न्यूनतम उपभोग को आदर्श बनाया है। मनुष्य की प्राकृत भावनाओं का संस्कार करके उसमें अधिकाधिक उत्पादन, समान वितरण तथा संयमित उपभोग की प्रवृत्ति पैदा करना ही आर्थिक क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्य है। इसमें ही तीनों का संतुलन है।'

साम्यवादी व पूँजीवादी विचारधाराएँ समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, विधिशास्त्र सभी को अर्थशास्त्र के हवाले कर देती है। अर्थशास्त्र की औद्योगीकरण–प्रवृत्ति ने वित्तीय सत्ता के केन्द्रीकरण को पोषण प्रदान किया है। इससे मानव जीवन का ही मशीनीकरण हो गया है। उपाध्याय धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र में पारस्परिक संतुलन के हिमायती हैं। इस संतुलन कार्य को वे 'सांस्कृतिक' कार्य मानते हैं तथा इस दृष्टि से अनुकूल अर्थायाम की स्थापना के हिमायती हैं।

❑ ❑ ❑

LUB's Gautam Buddha Nagar District unit conducted a meeting with a highly insightful session of National General Secretary Shri Om Prakash Gupta at LUB HQ, New Delhi. GB Nagar's activities & initiatives were warmly appreciated by all.

LUB's Gurugram Unit of Haryana celebrated 33rd Foundation Day in the presence of AIWC Member & State In-charge Shri Arun Bajaj, State GS CA Manoj Rungta, Gurugram-Manesar In-charge Shri Rakesh Gupta, Unit President Shri Vinod Gupta & GS Shri Vinod Wadhva and Treasurer Shri Pawan Gupta.

Against the Wind: *The Entrepreneur who Steers the Boat to Success*

Karmyogi
K. K. Seksaria
MD- UMA Plastics Ltd., Kolkata
President, LUB's South Sambhag, WB

Shri K. K. Seksaria is known for his hard work, sincerity, and unwavering commitment to his goals. A Chartered Accountant by profession, he also possesses a deep passion for literature and poetry. However, his journey to becoming a distinguished industrialist was far from easy. He embarked on his entrepreneurial journey in 1980, at a time when the decision to venture into business was particularly challenging. West Bengal was witnessing significant industrial unrest, with the growing influence of communist ideologies and the emergence of a trade union culture under the Left regime. Despite these formidable challenges, Shri Seksaria displayed remarkable courage and determination, laying the foundation for his future success in industry.

Reflecting on the past, Shri Seksaria remarks, **"The industrial environment was in turmoil and the odds were stacked against major organisations. However, I took it as a challenge. I firmly believe that an entrepreneur is like a sailor who can navigate and steer the boat even in the face of opposing winds."**

Today, he is an acknowledged leader in India's plastics and MSME sectors, with over 45 years of distinguished experience spanning profession, industry, entrepreneurship, and public life. As the Managing

Received the prestigious Modern Plastics Award at Narendra Modi Stadium, Motera, Ahmedabad, Gujarat

Director of UMA Plastics Ltd., he has successfully led the company for the past 26 years, transforming its flagship brand, Swagath Furniture, into one of India's most respected names in quality plastic furniture and a credible leader in stadium seating solutions.

Under his dynamic leadership, the company has diversified into innovative and premium ranges of plastic, metal, and modular furniture, while also establishing a strong presence in institutional and infrastructure projects across the country.

Company's Landmark Achievements: The company has undertaken the work of manufacturing and installing seating systems at some of India's most prestigious sports venues, a few of which are mentioned here-

- *Narendra Modi Stadium, Ahmedabad - the World's Largest Cricket Stadium*
- *Salt Lake Stadium, Kolkata- India's largest Football Stadium*
- *Eden Gardens, Kolkata- one of the World's Most Iconic Cricket Stadiums*
- *Arun Jaitley Stadium, New Delhi and numerous other stadiums across Chandigarh, Guwahati, Mizoram, Meghalaya, Jodhpur, Nathdwara, Raipur and other locations.*

As the President of PlastIndia Foundation, he played an instrumental role in establishing Plastindia International University, Vapi-the country's first dedicated university for plastics education, research, innovation, and skill development. Demonstrating his commitment to sustainability, he also spearheaded a unique initiative that achieved a Guinness World Record for creating the World's Largest T-Shirt made from recycled plastic bottles. The project was undertaken to raise awareness about solid waste management, plastic waste recycling, and environmental sustainability.

Earlier, as the Honorary Secretary and later President of the Indian Plastics Federation, he actively worked with the Govt. of West Bengal to promote the establishment of a Poly Park in Howrah. Throughout his distinguished career, he has remained committed to building robust knowledge, research, and skill-development infrastructure for the plastics industry in India.

Contribution to the MSME Sector

The cause of MSMEs has remained close to his heart for more than 35 years. Throughout this period, he has consistently represented and pursued issues concerning MSMEs before State & Central Governments, and various regulatory authorities. His unwavering commitment has significantly contributed to the MSME ecosystem, entrepreneurship, skill development, capacity-building initiatives, emerging entrepreneurs and start-ups.

He has also served as the Honorary Secretary and Vice President of the Indian Council of Small Industries and has been the organiser and promoter of numerous Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) and self-employment initiatives, helping nurture a new generation of entrepreneurs and job creators.

He has also been actively involved in the management and strategic development of various companies within the 66-year-old UMA Group, a diversified business conglomerate with interests in: Electricals and Electronics, LED Lighting, Engineering Products, Plastic, Steel, and Modular Furniture, Polymer Distribution, Plastic Products and Industrial Solutions.

Under his guidance and strategic vision, the UMA Group has expanded its presence across multiple sectors, building a reputation for quality, innovation, and sustainable growth.

As a committed industry leader, he has held several prestigious positions, including:

- Past President, Plastindia Foundation
- Past President, Indian Plastics Federation
- Past Co-Chairman, Petrochemical Committee, FICCI (2015–2018)

At present, he serves as a Member of the Governing Body of Plastindia International University.

Throughout his distinguished career, he has played an active role in the promotion, protection, and sustainable development of the plastics industry and the MSME sector in India.

Social, Literary and Spiritual Interests

The professional journey of Shri K. K. Seksaria exemplifies the spirit of entrepreneurship, industry leadership, institution building, and an unwavering commitment to nation-building through manufacturing excellence and MSME development.

Beyond business and industry leadership, he has actively contributed to a wide range of social, literary, and spiritual pursuits, including: Leadership positions in Lions Clubs International, Social service and community welfare initiatives, Skill development and self-employment programs, Journalism and literary activities, Poetry and creative writing, Spiritual studies and community development initiatives.

A Man of Many Dimensions

A Chartered Accountant by qualification, an industrialist by profession, and a poet and philanthropist by choice, Shri K. K. Seksaria is truly a man of many dimensions. His remarkable journey embodies entrepreneurship, institution building, manufacturing excellence, innovation, and visionary industry leadership.

Through his outstanding professional achievements, social commitment, and steadfast dedication to the growth of India's plastics industry and MSME sector, he has earned the distinction of being one of the most respected voices in Indian manufacturing and enterprise development. His life and work continue to inspire entrepreneurs, industry leaders, and future generations to combine business success with social responsibility and nation-building.

- ***Based on conversation with Entrepreneur & EC Member AIWC, Laghu Udyog Bharati Shri Paul Kumar Mitra @ Kolkata***

❑ ❑ ❑

Udyog Times Co-Editor Dr. Sanjay Mishra presented a copy of Swayamsiddha Special Edition to Hon'ble Governor of Rajasthan Shri Haribhau Kisanrao Bagde ji. He appreciated Laghu Udyog Bharati for its continuous efforts and impactful working for promoting MSMEs and inspiring women entrepreneurs.

LUB's UP State Secretary Shri Rajesh Singh presented a copyof Udyog Times to Shri Rajesh Chaudhary-AssistantDirector (MSME-DFO, Varanasi), and Shri Virendra Rana, Assistant Director (MSME, Varanasi).

An Industrial Awareness Program was organized by the Chandigarh unit.

Plastic Waste Management Rules (2016-2026) in India: An Impact Assessment

Utpad Update
Hiten Bheda
Chairman, Environment Committee
All India Plastics Manufacturers Association (AIPMA), Mumbai
hitenb@polymatindia.net

The Plastic Waste Management (PWM) Rules were introduced to tackle the growing issue of visible plastic waste largely emerging from plastic packaging on the principal of polluter pays. However, the burden largely shifted onto producers who introduced such packaging in the market making them responsible for the waste generated from their products. This was done through the concept of Extended Producer Responsibility (EPR), which shifted the burden of waste management from government authorities to Producers, Importers, and Brand Owners (PIBOs). The idea was simple: those who introduce plastic into the market must also ensure its proper collection, recycling, and disposal.

The journey began with the introduction of PWM Rules, **2016**, which laid the foundation of EPR in India. Under this framework, PIBOs were required to set up systems for collecting plastic waste and ensure that it was sent to authorized recyclers or disposal facilities. The rules also defined role of Urban Local Bodies (ULBs) in waste collection and segregation, while waste generators were expected to segregate waste at source. The scope of the rules was expanded to cover rural areas and multi-layered plastics (MLP), which were earlier not properly addressed. However, the system at this stage was quite basic. There were no clear targets for collection or recycling, monitoring was limited, and enforcement was weak, which led to inconsistent implementation across the country.

In **2018**, the focus shifted towards improving compliance. The amendment made it mandatory for

PIBOs to register with State Pollution Control Boards (SPCBs). This was an important step in bringing more companies into the formal system and ensuring that they could be monitored. While this improved visibility of stakeholders, enforcement mechanisms were still not strong enough to ensure full compliance.

The **2021** amendment brought stricter regulatory control, especially with the introduction of a ban on certain single-use plastics (SUP), which came into effect from **July 2022**. Items such as plastic cutlery, straws, and specific types of packaging were prohibited. At the same time, the minimum thickness of plastic carry bags was increased to 120 microns to promote reuse and make recycling more viable. These changes were aimed at reducing the use of low-value, non-recyclable plastics and improving overall waste management practices.

A major shift happened in **2022** with the introduction of detailed EPR Guidelines, which fundamentally changed how the system operated. For the first time, clear quantitative targets were introduced, requiring PIBOs to manage an amount of plastic waste equivalent to what they put into the market. Plastic packaging was also categorized into four types rigid, flexible, multi-layered, and compostable to make tracking and compliance easier. One of the most important developments was the introduction of a credit-based

system. Under this system, recyclers generate EPR credits when they process plastic waste, and PIBOs are required to purchase these credits to meet their obligations. This created a market-based approach to compliance. Alongside this, a centralized online portal managed by the Central Pollution Control Board (CPCB) was launched to handle registration, reporting, and tracking. The introduction of environmental compensation provisions also meant that non-compliance could lead to financial penalties, making the system more accountable.

Later in **2022,** these EPR Guidelines were formally incorporated into the PWM Rules, giving them legal backing. This made compliance through the CPCB portal mandatory and strengthened the enforcement powers of SPCBs. As a result, EPR requirements became more standardized and enforceable across the country.

During **2023** and **2024**, the emphasis was on tightening the system further. Registration became mandatory before starting business operations, and integration with GST systems was introduced to improve transparency and traceability of transactions. Companies were required to file annual returns through the portal, and penalties for violations were increased. These steps were aimed at closing compliance gaps and ensuring better monitoring of plastic waste flows.

In **2025**, there were no major structural changes, but efforts continued to improve the functioning of the system. The focus remained on strengthening portal performance, improving the efficiency of the credit mechanism, and enhancing data tracking and monitoring processes.

The **2026** amendment introduced a more practical approach by allowing companies to carry forward unmet EPR targets for up to three years. However, this flexibility came with a condition that the pending targets must be fulfilled gradually, with at least one-third cleared each year. This change recognized the operational challenges faced by businesses while still ensuring that long-term compliance goals are not compromised.

Overall, the EPR framework under the PWM Rules has evolved significantly over the past decade. What started as a basic concept in **2016** has developed into a structured, digital, and market-driven system by **2026.** The introduction of targets, credit mechanisms, and centralized monitoring has improved accountability and transparency. However, challenges still remain, including gaps between waste generation and recycling, lack of clarity in credit pricing, technical issues with the portal, and limited participation of MSMEs. Addressing these issues will be important to ensure that the system works effectively and achieves its objective of sustainable plastic waste management in India.

EPR Compliance and MSME's

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a significant role in India's plastic value chain, especially in manufacturing, converting, and recycling activities. However, with the strengthening of Extended Producer Responsibility (EPR) under the Plastic Waste Management Rules, compliance has become increasingly challenging for this segment. While the intent of EPR is to improve accountability and ensure proper waste management, the current system tends to be more conducive for large, organized players, often leaving MSMEs struggling to keep up.

One of the biggest challenges for MSMEs is the **high cost of compliance**. Expenses related to EPR registration, purchasing credits, maintaining documentation, and meeting reporting requirements can be substantial. Unlike large corporations, MSMEs operate on thin margins and often lack the financial capacity to absorb these additional costs. This makes compliance not just difficult, but in some cases, commercially unviable.

Another major issue is the **complexity of the digital portal and reporting system**. The EPR portal requires regular data uploads, documentation, and tracking of transactions, which can be difficult for MSMEs that do not have dedicated compliance teams or technical expertise. Frequent technical glitches, lack of user-friendly features, and absence of multilingual support further add to the burden.

MSMEs also face difficulties in the **EPR credit mechanism**. They often have limited understanding of how credits are generated, traded, and utilized. In many

cases, smaller recyclers accumulate credits but are unable to sell them due to lack of market access or awareness. On the other hand, small brand owners may struggle to find reliable suppliers of credits at reasonable prices, leading to inefficiencies and added costs.

The issue of **GST and invoicing compliance** is another pain point. Many MSMEs operate under simplified GST structures or exemptions, but the EPR system often requires strict invoice validation, QR codes, and detailed documentation. This mismatch leads to frequent rejection of invoices and delays in credit generation.

Infrastructure constraints further complicate compliance. Many MSMEs, especially recyclers, operate in areas where **collection and aggregation systems are weak**. Access to consistent, clean, and segregated plastic waste is limited, which affects their ability to generate EPR credits and run operations efficiently.

Further, there is a lack of **clear guidance and handholding support**. MSMEs often struggle to interpret regulatory requirements, and there is limited access to training, awareness programs, or responsive helpdesks. This results in confusion, errors in compliance, and in some cases, unintentional non-compliance.

Lastly, the presence of **informal and unregistered players** creates an uneven playing field. MSMEs that try to comply with regulations face higher costs, while non-compliant entities continue to operate without accountability, offering cheaper services and distorting the market.

While the EPR framework is a necessary step towards sustainable plastic waste management, its current design places a disproportionate burden on MSMEs. To ensure effective implementation, there is a need for simplified compliance processes, cost-sharing mechanisms, better digital infrastructure, and targeted support for smaller businesses. Without addressing these issues, MSME participation will remain limited, ultimately affecting the overall success of the EPR system.

It is to be noted that need for plastic waste management now far exceeds the objective of only "Swachh Bharat" but also includes sustainability, circularity, carbon zero and above all resource efficiency. For a country with small per capita consumption at present but aspiration to be 30 trillion economy by 2047 as part of vision of Vikashit Bharat, it is imperative that Plastic Waste Management is looked as an industrial activity and recycling is adequately incentivised for obtaining meaningful outcome of EPR.

Overall Conclusion

In Conclusion, the EPR system in India has come a long way. What started as a basic idea has now become a more structured system with targets, tracking, and accountability. It has improved transparency and pushed companies to take responsibility for the plastic they put into the market.

But on the ground, things are still not that smooth. There are practical issues like weak infrastructure, inconsistent enforcement, unclear pricing of credits, and a heavy compliance burden especially for MSMEs. Many smaller businesses are finding it difficult to keep up with the system.

Going ahead, the focus should be on fixing these gaps making the system simpler, improving the portal, ensuring fair pricing, and supporting MSMEs. At the same time, better collection systems and proper inclusion of the informal sector are equally important.

In short, EPR has set the right direction for plastic waste management in India. Now the priority should be to make it work smoothly in real life, so that everyone can comply without unnecessary difficulty.

❑ ❑ ❑

National Technology Day was celebrated by LUB's Kashi Prant in association with Central Silk Board, Ministry of Textiles, Govt. of India at Varanasi on 11th May.

लघु उद्योग भारती

Dear Pharma Fraternity

We delighted to inform you that
Laghu Udyog Bharati-Pharma Committee
going to organise....

LUB PHARMA CONCLAVE

On

25th July 2026
(Saturday)

AT

INDIA HABITAT CENTRE

Lodhi Road, Nr India Gate

• NEW DELHI •

Shri J P NADDA
Hon'ble Union Minister
of Health & Family Welfare
and Chemicals & Fertilizers
Government of India

Shri PIYUSH GOYAL
Hon'ble Union Minister
of Commerce & Industry
Government of India

Towards
VIKSIT BHARAT 2047

Shri Manoj Joshi, I.A.S.
Secretary
Department of Pharmaceuticals
Govt. of India

Ms. Punya Salila Srivastava, I.A.S.
Secretary Health & Family welfare
Govt. of India

Shri Rajesh Aggarwal, I.A.S.
Secretary Commerce & Industry
Govt. of India

Dr. Rajeev Singh Raghuvanshi
Drugs Controller General (India)
CDSCO

TO ADDRESS KEY ISSUES FOR

- Roadmap for Pharma MSME'S
- Domestic & Export Market
- For Viksit Bharat 2047 Vision & Strategy

For Registration & Enquiry
Please contact to pharma committee

Contact Details :
9779021318, 9826698084, 9810820562, 9326941001, 9999984555, 9254124143
Email: lub.pharma@gmail.com

Warm regards
TEAM LUB PHARMA

Innovation: Easy, Effective & Economical Tool for Asset Creation

Insights
Mahesh Jogani
Expert in Reinforcement Technologies
Member, LUB Konkan Anchal, Maharashtra
joganireinforcement@gmail.com

Innovation and entrepreneurship are essential pillars of a successful commercial venture. Entrepreneurs continuously explore how these two forces drive growth, create value, and fuel the success of an enterprise."

There is no doubt that innovation remains critically important for both individuals and society. In today's rapidly changing world, its significance is even greater than in the past. As industrial competition intensifies and global markets become increasingly competitive, companies must continuously introduce innovative products and services to remain relevant and successful.

To survive and grow, organizations need creative and inventive employees whose fresh ideas and novel solutions are essential for sustained competitiveness and long-term success. Consequently, modern society requires capable individuals who can address emerging challenges through innovation and contribute ideas that drive the development and expansion of products, services, and markets.

Contemporary society is, without question, heavily dependent on innovation, and the future will be shaped by those who can innovate effectively. Yet, despite its undeniable importance to organizational growth and societal progress, innovation remains a complex phenomenon that is not fully understood. Its nature, drivers, and processes continue to be explored by researchers, business leaders, and entrepreneurs alike.

Innovation is the process of executing an idea that addresses a specific challenge and creates value for both the individual and society. It is a continuous and never-ending journey of improvement, adaptation, and problem-solving. While many people generate ideas, few successfully translate them into action. However, innovation is not simply about having a brilliant idea that changes the world. True innovation is far more complex-it requires vision, execution, persistence, and the ability to create meaningful and lasting impact.

Image Bulb Thinking Innovation

Shri Karsanbhai Patel did not invent detergent. His true innovation lay in transforming the way it was marketed and distributed. Through an efficient distribution network, a compelling money-back guarantee, and an affordable price point, he created the remarkable Nirma success story. In doing so, an Indian entrepreneur challenged multinational corporations on their own turf and rewrote the rules of the detergent business in India. His journey demonstrates that innovation is not always about inventing a new product; often, it is about finding better ways to deliver value to customers.

What is important to understand is that innovation does not have to be grand or revolutionary to be effective. More often, successful innovation is simple, practical, and focused on addressing a specific need or solving a particular problem. It is usually best to start small, with limited resources, a small team, and a narrowly defined market. This approach provides the flexibility and time

needed to make the adjustments and improvements that are inevitably required during the early stages of development.

Innovation should also be designed with people in mind. Since innovations are ultimately implemented, used, and managed by ordinary individuals, they should not be unnecessarily complex or overly sophisticated. The most impactful innovations are often those that are easy to understand, simple to adopt, and capable of delivering clear value to their users.

India has long established itself as the world's leading outsourcing destination, particularly for global technology companies. However, in the era of the Fourth Industrial Revolution, the country has a unique opportunity to redefine its role in the global economy and emerge as a hub of innovation and entrepreneur- ship.

Encouragingly, India is witnessing the rapid growth of a vibrant start-up and innovation ecosystem. This transformation is reflected in the Global Innovation Index, where the country's ranking improved significantly from 81st position in 2015 to 52nd in 2019. The rise of innovative enterprises, technology-driven solutions, and entrepreneurial talent demonstrates India's growing capacity not only to provide services to the world but also to create products, technologies, and business models that can shape the future.

There is little doubt that technological advancements will continue to transform the way we live and work. In the years ahead, innovations such as autonomous vehicles and intelligent robots may become an integral part of everyday life. While the future promises remarkable technological breakthroughs, it is equally important to recognize the profound impact technology is already having on our lives today.

A look around us reveals that Artificial Intelligence (AI) is no longer a futuristic concept-it is a present-day reality. From software that anticipates our needs to supply chains that make real-time decisions and robots that adapt to changing environments, AI is increasingly embedded in the modern world. Leading companies of the 21st century are already leveraging AI to drive innovation, improve efficiency, and accelerate growth.

The message for businesses is clear: organizations that understand and harness the power of AI can gain a significant competitive advantage, while those that fail to adapt risk being left behind. As technology continues to evolve, the ability to embrace innovation and integrate AI into business strategies will be a key determinant of future success.

The interconnected interactions between humans and machines-human-to-human, human-to-machine, and machine-to-human-will continue to deepen and expand, creating new opportunities for collaboration, efficiency, and innovation.

❑ ❑ ❑

LUB's Udaipur Units of Rajasthan celebrated 33rd Foundation Day in the presence of State President Shri Yogendra Sharma, Chittor Anchal GS Shri Praveen Gupta and In-charge Swayamsiddha Smt. Reena Rathore

Business Ecosystem in Karnataka - An Analysis

Wide Angle
M. Ravi Kumar
State General Secretary, LUB Karnataka
updates@lubkarnataka.org

Karnataka is one of the pioneering states in India that has consistently focused on industrial development and contributed significantly to the nation's GDP. Even before Independence, the Maharajas of Mysuru were known for their visionary efforts in establishing industries and promoting economic activities in the erstwhile Mysuru Province.

Sir M. Visvesvaraya, one of India's greatest engineers and statesmen, played a transformative role in shaping Karnataka's industrial future. He coined the famous phrase, "Industrialize or Perish," which later became a guiding principle for India's industrial planning.

Karnataka has been blessed with a strong industrial ecosystem that attracts investments not only from across India but also from global investors. The state is widely recognized as the 'Silicon Valley of India,' while its capital city, Bengaluru, is known as the *'Startup Capital of India.'* The state is a premier hub for innovation and is home to numerous technology companies, unicorn startups, venture capital firms, and research institutions. Karnataka also hosts 19 Central Public Sector Enterprises (CPSEs) with operational and registered offices in the state.

To ensure focused industrial growth, the Govt. of Karnataka has established dedicated ministries for MSMEs, Medium Industries, and Large Industries. Furthermore, the state formulates a comprehensive Karnataka Industrial Policy every five years to strengthen industrial development.

The vision of the Karnataka Industrial Policy 2025-30 is:

"To position Karnataka as the No.1 destination in Asia for high-technology manufacturing investments through equitable and sustainable development."

Positive Factors Driving Industrial Growth in Karnataka:

Strong Industrial Infrastructure

The Karnataka Industrial Areas Development Board (KIADB) operates more than 215 industrial areas spread across approximately 86,849 acres in all 31 districts of Karnataka, creating a strong industrial base for investors.

Excellent Road Connectivity

Karnataka has one of the best road networks in India. The state has the second-largest network of state highways in the country and is connected by 14 National Highways, facilitating smooth industrial transportation and logistics.

Robust Railway and Urban Transport Network:

The state possesses an extensive railway network. In addition, Bengaluru's Metro Rail and suburban rail systems have significantly improved urban connectivity and industrial mobility.

Strong Air Connectivity

Karnataka has nine operational airports, including two international airports and seven domestic airports, supporting both passenger and cargo transportation efficiently.

Port Infrastructure

The state has three operational ports, including one major port and two minor ports. Collectively, these ports handle nearly 50 million metric tons of cargo annually, strengthening Karnataka's export and import capabilities.

Progressive Industrial Policies

The Karnataka Industrial Policy 2025-30 emphasizes:

- GDP acceleration
- Employment generation
- Innovation-driven growth

These themes form the foundation of the state's industrial strategies and initiatives.

Sector-Specific Policies

Karnataka has introduced dedicated policies for key sectors, including:

- Aerospace and Defence Policy 2022-27
- Electronics Components Incentive Scheme 2020-25
- Textile and Garment Policy
- Karnataka Tourism Policy 2024-29
- Renewable Energy Policy 2022-27
- Drone and Space Technology Promotion under A&D Policy
- Biotechnology Policy 2024-29

The Industrial Policy 2025-30 also gives special focus to: Machine tools, Pharmaceuticals, Automobiles, Green Hydrogen, Software and IT Services

Specialized Industrial Zones

Karnataka has developed specialized industrial ecosystems such as:

- Aerospace Parks
- Biotechnology Parks
- Global Capability Centres (GCCs)

These initiatives have significantly enhanced Foreign Direct Investment (FDI) inflows into the state.

SME Connect Initiative

The Karnataka Government's SME Connect 2025 initiative aims to prepare SMEs for opportunities emerging from Industry 4.0 technologies and digital transformation.

Single Window Clearance System

The Government has introduced a new Single Window Clearance System to provide a seamless, transparent, and efficient investment experience by reducing procedural delays and simplifying approvals.

Negative Factors Affecting Industrial Development in Karnataka

- **Lack of Basic Amenities in Industrial Areas**

Many industrial lands allotted by development authorities still lack essential facilities such as:

- Reliable power supply
- Proper infrastructure
- Clear title deeds
- Financial support mechanisms

Only a few districts possess fully developed industrial infrastructure.

High Cost of Industrial Land

Industrial land prices are often beyond the reach of small and micro entrepreneurs, making industrial expansion difficult for MSMEs.

High Industrial Power Tariffs

The per-unit cost of electricity for industries remains high. Despite repeated representations by industrial associations, adequate corrective measures have not yet been implemented.

Weak Infrastructure in Tier-2 and Tier-3 Cities

Industrial infrastructure in smaller cities and towns continues to face major challenges due to inadequate facilities and poor connectivity.

Inadequate Warehousing and Storage Facilities

Karnataka lacks sufficient modern warehousing and storage infrastructure. This results in:

- Increased raw material costs
- Higher transportation expenses
- Escalation in final product pricing

Limited Awareness of Govt. Schemes

Several beneficial schemes, including Cluster Development Schemes, are not effectively promoted. Lack of awareness among small entrepreneurs has hindered technology adoption and industrial scaling.

Rising Cost of Living

In highly industrialized districts, the cost of living has increased significantly. This has directly impacted:

- Wage structures
- Employee welfare costs
- Industrial operating expenses

Concerns Regarding Minimum Wage Revision

The recent notification issued by the Labor Department in May 2026, proposing up to a 60% increase in minimum wages in certain zones, has faced strong opposition from employers and industrial bodies. The matter is currently under consideration before the High Court.

Complicated Land Conversion Procedures

The process of converting land for industrial purposes remains lengthy and complex. Lack of coordination between the Revenue Department and Labor Department further delays approvals.

Challenges in Single Window Clearance for MSMEs

Although the Single Window Clearance System works relatively well for large and mega industries, small and medium enterprises still face:

- Lengthy approval procedures
- Multiple departmental clearances
- High compliance costs for obtaining NOCs

❑ ❑ ❑

LUB's Surat District unit conducted Entrepreneur Conference-2026 on the theme 'Echoes of Industry for Nation-Building' on 4th May.

National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji stated that during the British and Mughal rule, India's small industries were weakened, whereas at one time India was the "Golden Sparrow" because every hand had employment and India supplied textiles to the world. He said that for the past 33 years, Laghu Udyog Bharati has been working as the voice of the MSME sector, strengthening the backbone of the country's economy. He urged entrepreneurs to use technology and artificial intelligence (AI) to establish industries at global level.

Surat President Shri Ramavatar Parikh stated that LUB is working towards a Skill Development Centre, through which training can be provided to migrants and needy people. Gujarat President Shri Ishwarbhai Patel shed light on the organization's activities. Meanwhile, former National President Shri Vajubhai Vaghasiya provided information about the IIF program to be held in October.

During the program, five commendable entrepreneurs- Vampum Synthetics, Gauri Putra, Devshri, Olzin, and Yug Fashion were honored with the 'Outstanding Entrepreneur Award' for contribution to the industrial world.

The organisation appointed Shri Hansraj Jain as Sambhag VP and Shri Rajendra Choudhary & Shri Vijay Mangukiya as Sambhag Secretary.

On this occasion, Former National President Shri Baldevbhai Prajapati, Shri Sanwar Prasad Budhia, Shri Dashrath Shekhawat, Joint Commissioner-Industries Shri J.B. Dave, Joint Secretary Shri Pankaj Sharma, Treasurer Shri Vinod Saraswat, Unit Presidents- Shri Ganpat Bhati, Shri Shyam Tawaniya & Shri Hariom Swami, entrepreneurs Shri Ashok Shah, Shri Vijay Chaumal, Shri Babu Bhai Paliwal & Shri Gopal Parikh. The program was conducted by Shri Virendra Rajawat. General Secretary Shri Satish Savani expressed gratitude.

❑ ❑ ❑

LAGHU UDYOG BHARATI, CHANDIGARH

SAAK
auto accessories

World Class Car Accessories
& Upholsteries
That Define your Style !

Stop Pollution · Stop Environment · Saving Money

Good on Money Saving, Good for Environment !

Plot No. 423, Industrial Area, Chandigarh | Call : 99151 00055

Follow us on /SAAKAUTOS | www.saakauto.com

Driving a 4 Wheeler
No Even More Economical

Fitted with imported GRECO CNG Car Kit

JAI CASTINGS
NFOL ENTERPRISES
ALDICA INDUSTRIES

Aluminium Casting, CI Casting,
Ceiling Fan Parts

Office : 665, Industrial Area, Phase-I, Chandigarh
Phone : 0172-2651553, 92162-40540
E-mail : nfolenterprises@gmail.com, nfolenterprises@hotmail.com

Rakesh R. Aggarwal
Proprietor
92162-40440

SUNIL PROPERTIES
REAL ESTATE CONSULTANT

SALE PURCHASE / LEASING ALL KIND OF PROPERTIES
INDUSTRIAL, COMMERCIAL & RESIDENTIAL ALL OVER TRICITY

Contact
+91 9417200897, 9779779920, 8427787775

Address
73, Industrial Area, Ph-II, Chandigarh-160002
Email: sunilproperties@gmail.com

SONALAC
PAINTS

SONALAC PAINTS AND COATINGS LIMITED

Leading Manufacturer of Wall Putty & Tile Adhesives

Regd. & Head Office : 766, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160 002 (India)
Web Site : www.sonalacpaints.in; Email : info@sonalacpaints.in
Phone : 0172 - 5086150, 9872869389, 9988322800

झारखंड में लघु उद्योगों से स्वदेशी उत्पादन और संभावनाएं

स्वावलंबन

बिनोद कुमार अग्रवाल
प्रदेश महामंत्री
लघु उद्योग भारती, झारखण्ड
parrotmasala@yahoo.com

लघु उद्योग की जब भी बात होती है, झारखंड की चर्चा बेहद प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और मेहनतकश लोग लंबे समय से स्वदेशी उत्पादन की ताकत बने हुए हैं। आधुनिक औद्योगिक ढांचे के बीच भी झारखंड में लघु और कुटीर उद्योग न केवल स्थानीय रोजगार का आधार हैं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और स्वदेशी पहचान को भी जीवित रखे हुए हैं। राज्य सरकार की योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना इन लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

झारखंड प्रदेश का हर जिला अपने अनोखे परंपरागत स्वदेशी उत्पादों के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि राज्य के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों की राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग निरंतर बनी रहती है। हजारीबाग की सोहराय पेंटिंग की ख्याति देश–विदेश में है और उसका निर्यात भी हो रहा है। खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सरायकेला–खरसावां जिलों के बांस एवं लकड़ी शिल्प की बाजार में बड़ी मांग है। जमशेदपुर–सिंहभूम के लोहे और धातु आधारित छोटे उद्योग भी प्रसिद्ध हैं।

घरेलू सजावट से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुएं यहाँ के कारीगरों के हुनर का प्रमाण हैं। सरायकेला–खरसावां में हल्दी की खेती उम्दा क्वालिटी की होती है। रांची, दुमका और साहिबगंज क्षेत्र की पारंपरिक आदिवासी ज्वेलरी की पहचान आज वैश्विक मंच तक पहुँच चुकी है। चांदी, मनके और पीतल से बनी ज्वेलरी का क्राफ्ट आधुनिक डिजाइनरों को भी आकर्षित करता है।

झारखंड के गोड्डा–दुमका–पाकुड़ का तसर सिल्क अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना चुका है। तो वही यहां के घर–घर में बनते अचार और मसालों को अब छोटे उद्योग भी ब्रांडिंग कर बाजार में उतार रहे हैं। हजारीबाग, बोकारो और रांची में मसाला और प्रोसेस्ड फूड के लघु उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं।

बुंडू तमाड़ में टमाटर की खेती उम्दा क्वालिटी की होती है। इससे सम्बद्ध फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बड़ी संख्या में लगाई जा सकती हैं। प्रदेश से इमली भी अभी तक बाहर निर्यात की जा रही थी, लेकिन अब इसके उद्योग स्थापित हो रहे हैं जहां इसका पेस्ट बनाया जायेगा।

झारखंड के तसर सिल्क की पहचान क्वीन ऑफ सिल्क के रूप में राष्ट्रीय बाजार में है। हस्तशिल्प और लोककला की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में झारखंड की कृतियों को सराहना मिलती रही है। अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों तक यहाँ के हैंडीक्राफ्ट निर्यात होते हैं। वहीं, आदिवासी ज्वेलरी फैशन इंडस्ट्री में नये डिजाइन ट्रेंड सेट कर रही है।

झारखंड के कुटीर और लघु उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही नहीं, बल्कि स्वदेशी आत्मनिर्भरता की असली तस्वीर हैं। झारखंड का हर उत्पाद यह संदेश देता है कि 'स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर भारत बनाइए' का सपना यहीं से साकार हो सकता है।

झारखंड की मिट्टी में अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। यहाँ का हर जिला अपने विशिष्ट उत्पाद के लिए जाना जाता है। आज राज्य के करीब ढाई लाख लघु उद्योग 15 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार दे रहे हैं। यह केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं दे रहे, बल्कि स्वदेशी आत्मनिर्भरता का आधार भी हैं। यदि इन उद्योगों को आधुनिक तकनीक, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ई–मार्केटिंग से जोड़ा जाए, तो झारखंड का हर उत्पाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ग्लोबल ब्रांड बन सकता है। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ लघु उद्योग भारती भी लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर स्वदेशी वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग करना ही सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारी सबसे बड़ी भूमिका होगी।

❑ ❑ ❑

LUB's Expanding Efforts in Industry Collaboration, Innovation & Capacity Building

The month of May-2026 witnessed several impactful initiatives under the Industry Academia & Technology Transfer Vertical of Laghu Udyog Bharati (LUB), focused on strengthening MSMEs through institutional collaborations, workforce development, succession planning, innovation support, and technology-driven problem solving.

A major milestone was achieved on 25th May with the formal signing of a MoU between **Laghu Udyog Bharati** and **Dr. B.R. Ambedkar National Institute of Technology (NIT) Jalandhar.** The MoU was signed by Prof. Binod Kanaujia, Director, NIT Jalandhar, and Adv. Arvind Dhumal, National Vice President-LUB. This collaboration marks an important step towards strengthening industry-academia partnerships and fostering innovation, research collaboration, technology transfer, internships, entrepreneurship, consultancy support, and skill development initiatives for MSMEs and students alike.

Further strengthening its focus on human resource development and organizational excellence, LUB, in collaboration with Vidyalankar Polytechnic, Mumbai, organized a Two-Day Online Workshop on **'Workforce Retention & Productivity - Skilling, Motivating & Retaining Talent'** on 22nd and 23rd May, with participation from around 50 LUB members from across the country. The sessions conducted by **Dr. Pooja Raj Srivastava** provided practical and implementation-oriented insights on employee engagement, workforce productivity enhancement, motivation strategies, and talent retention practices relevant for MSMEs. Members particularly appreciated the self-analysis and assessment checklists prepared separately for MSMEs, which were found to be highly introspective and useful for organizational evaluation and improvement.

On 15th and 16th May, LUB successfully organized an Exclusive Session on '**Family Business Succession & Longevity**' at the LUB Head Office, Delhi. The two-day programme featured highly enriching expert sessions by **Prof. Toshio Goto from Japan University of Economics** and **Dr. Hitesh Shukla from Saurashtra University**, focusing on succession planning, organizational values, governance systems, leadership transition, sustainability, and longevity in family businesses. The program was graced by the

presence of Shri Om Prakash Gupta LUB's National General Secretary, Smt. Anju Bajaj National Secretary, Smt. Aarti Sehgal General Secretary-LUB Delhi, and Smt. Jayanti Goela-National Coordinator - Industry Academia & Net Zero. More than a conventional knowledge session, the program evolved into a highly interactive platform for practical learning, open dialogue, and experience sharing among participating business families. A special highlight of the program was the dedicated one-to-one interaction sessions where participants personally discussed their business concerns, succession challenges, and future vision with the experts.

Apart from these initiatives, Round 3 of collecting technical and management problem statements from LUB members was also circulated during the month. Members were encouraged to share real-time challenges being faced in their industries so that these issues can be addressed through the Industry Academia & Technology Transfer Vertical by connecting industries with relevant institutions, researchers, experts, and student innovators for practical and scalable solutions.

Simultaneously, the vertical is actively working towards expanding its outreach across the country through the formation of dedicated state-level teams under the Industry Academia & Technology Transfer initiative.

Through these continuous efforts, Laghu Udyog Bharati remains committed towards building meaningful industry-academia linkages and empowering MSMEs through knowledge sharing, innovation, collaborative research, skill development, and sustainable growth initiatives.

❑ ❑ ❑

INDIA INDUSTRIAL FAIR 2026

IIF Chhattisgarh-2026 Update

LUB's delegation of Chhattisgarh Team led by State President Smt. Sipi Dubey invited Finance Minister Shri Om Prakash Choudhary and President CSIDC Shri Rajiv Agarwal for IIF-2026 at Raipur.

LUB's Beawar unit of Rajasthan organized an important meeting for initiating the construction of the Skill Development Center. Under the guidance of former National President Shri Ghanshyam Ojha, discussions were held on the action plan, preparations, and organizational coordination. Shri Ajay Khandelwal, Shri Deepak Jhanwar and other entrepreneurs were present.

स्वरोजगार से स्वावलंबन और स्वाभिमान के पर्याय बने पाली में बिखरेगा कौशल का 'प्रकाश'

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कौशल विकास केंद्र का किया शिलान्यास
संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास कार्य का विस्तार करने पर बल

कौशलम
राहुल मेहता
संयुक्त सचिव, जोधपुर अंचल
लघु उद्योग भारती, राजस्थान

राजस्थान का पाली कस्बा बीते कुछ वर्षों से कौशल विकास के पर्याय के रूप में विकसित हो रहा है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के प्रबल पैरोकार के तौर पर अपनी पहचान स्थापित करने वाले संगठन लघु उद्योग भारती ने अपनी स्थानीय टीम के साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कौशल विकास के ऐसे प्रकल्प शुरू किये जिनकी सफलता से उत्साहित होकर संगठन ने पाली के पुनायता औद्योगिक क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र की स्थापना का संकल्प लिया। भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इसी केंद्र का शिलान्यास 22 मई को किया।

कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़, सांसद श्री पीपी चौधरी, पाली के पूर्व विधायक श्री ज्ञानचंद पारख, बाली विधानसभा से विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, मारवाड़ जंक्शन के विधायक श्री केशाराम चौधरी सहित बड़ी संख्या में उद्यमीगण एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोविड–19 के दौर में जब सभी घरों में कैद हो गए थे तब आरएसएस व लघु उद्योग भारती ने महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का विचार किया। चूड़ियों पर नगीने लगाने की मशीन दी, मेहंदी, कंप्यूटर और सिलाई का काम सिखा कर 15 हजार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने इस केन्द्र को महिलाओं के साथ युवाओं के लिए लाभदायक बताया।

पाली में कौशल विकास की सफल पटकथा लिखने वाले लोकप्रिय विधायक श्री ज्ञानचंद पारख का मानना है कि देशभर में कौशल का पाली मॉडल एक मिसाल बन चुका है, लेकिन इस केंद्र के निर्माण से निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र की युवा पीढ़ी के जीवन में भी कौशल का प्रकाश उदय होगा और इससे न केवल उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, साथ ही उद्योगों को भी कुशल कार्मिक उपलब्ध हो सकेंगे।

लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष और पाली की कौशल टीम के प्रमुख स्तम्भ श्री विनय बंब ने बताया कि संगठन की ओर से कौशल विकास केंद्र के इस प्रस्तावित भवन–निर्माण के लिए दानदाताओं ने भी आगे बढ़कर आर्थिक सहयोग करने की पहल की। ग्राउंड फ्लोर के निर्माण में जालोर और पाली से जुड़ी और हैदराबाद रह रही प्रवासी उद्यमी श्रीमती भगवती महेश बलदेवा आर्थिक सहयोग करेंगी। इसी तरह प्रथम तल के लिए सलवार–सूट्स बनाने वाले ख्यात उद्यमी और प्रांजुल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्री पीयूष गोगड़ और द्वितीय तल के लिए सूर्यज्योति फाउंडेशन के श्री अमरचंद अनिलकुमार समदड़िया ने सहयोग करने की घोषणा की। ताड़केश्वर रामेश्वर, विश्वास इंडस्ट्रीज और वीतराग फैब्रिक्स से भी स्किल सेंटर विकसित करने के लिए आर्थिक सहयोग के लिए आश्वस्त किया गया है।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इन सभी भामाशाहों का पुष्पहार व शॉल ओढ़ा कर स्वागत किया। इसी अवसर पर कार्यक्रम में मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ और सांसद श्री पीपी चौधरी ने भी 25–25 लाख रुपए, बाली विधानसभा से विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने 20 लाख रुपए एवं मारवाड़ जंक्शन के विधायक श्री केशाराम चौधरी ने 10 लाख रुपए इस केंद्र के लिए आर्थिक सहयोग के तौर पर प्रदान करने की घोषणा की।

गौरतलब है कि 10 हजार स्क्वायर फीट में बनने वाले तीन मंजिला कौशल विकास केंद्र का निर्माण दो वर्ष की अवधि में पूरा किया जायेगा। केंद्र में विविध कौशल के प्रशिक्षण के साथ लैब व रिसर्च सेंटर का प्रावधान भी रखा गया है।

संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास कार्य का विस्तार करने पर बल

लघु उद्योग भारती की ओर से कौशल विकास को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक गति प्रदान करने के उद्देश्य से 18 मई को जयपुर स्थित सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र में महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई।इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चन्द्र जी ने कहा कि कौशल विकास केवल प्रशिक्षण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से समाज की आवश्यकताओं को समझते हुए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास का आदर्श मॉडल बनाने हेतु सामूहिक प्रयास पर बल दिया।

बैठक में राजस्थान के तीनों अंचल चित्तौड़, जोधपुर एवं जयपुर से प्रमुख पदाधिकारियों ने सहभागिता की। प्रदेश में कौशल विकास कार्यों के व्यापक विस्तार की आवश्यकता, कार्यप्रणाली एवं संभावनाओं पर श्री रवींद्र जाजू ने भूमिका प्रस्तुत की। बैठक में यह जानकारी साझा की गई कि देशभर में संचालित 37 कौशल विकास कार्यों में से 17 केवल राजस्थान प्रदेश में संचालित हो रहे हैं, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

वर्तमान में राजस्थान प्रदेश में जोधपुर, पाली, बालोतरा, जालौर, बीकानेर, शिवगंज, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, ब्यावर, जयपुर, अलवर सहित विभिन्न स्थानों पर कौशल विकास केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों

पर डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, डिजिटल मित्रा, बाजरा आधारित उत्पाद प्रशिक्षण, मेहंदी, मशरूम उत्पादन, सौंदर्य साज–सज्जा, चूड़ी पर नगीनें लगाने, मिलेट्स कुकिंग, केक–निर्माण, सिलाई–प्रशिक्षण, क्रोशिया, आर्ट एंड क्राफ्ट, पैकिंग एवं एम्ब्रॉयडरी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है एवं स्किल इंडिया वर्कशॉप जैसे प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं। बैठक में देशभर में कौशल विकास कार्य स्थानों की संख्या 100 करने का संकल्प लिया गया जिसमें राजस्थान की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया गया। कौशल विकास कार्य प्रारम्भ करने हेतु चिन्हित स्थानों में चित्तौड़ अंचल में उदयपुर, किशनगढ़, राजसमन्द, अजमेर, कोटा, बांसवाड़ा, बारां, सागवाड़ा जयपुर अंचल में नीमराना, चूरू, सीकर, भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी और जोधपुर अंचल में नागौर, नोखा, हनुमानगढ़ आदि सम्मिलित हैं।

संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से संवाद किया। प्रशिक्षण में प्लंबिंग, डिजिटल सेवा, खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित कौशल को प्रशिक्षणों को शामिल करने पर बल दिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयों, औद्योगिक समूहों एवं अन्य संस्थाओं के साथ शैक्षणिक, तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संबंधी एमओयू की जानकारी आगामी बैठकों में प्रस्तुत की जाएंगी। अंचलवार बैठकों का आयोजन कर आगामी कार्ययोजना तैयार की गई। चित्तौड़ अंचल से श्री प्रवीण टांक व श्री दीपक शर्मा, जोधपुर अंचल से श्री हरीश लोहिया व श्री अशोक गहलोत और जयपुर अंचल से श्री मनीष जौहरी और श्रीमती वैशाली वशिष्ठ को दायित्व दिया गया। इस दौरान 'एक जिला– एक कार्यकर्ता– एक कार्य' के लक्ष्य के साथ प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक कौशल विकास कार्य को प्रारम्भ करने का संकल्प लिया। इससे पूर्व श्री महेंद्र खुराना ने सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र में संचालित स्टार्टअप, गारमेंट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट तथा सेना एवं सुरक्षा बलों से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी दी।

❑❑❑

An important meeting was conducted by Jalore unit on organizational matters, membership, LEAP registration, skill development, and related topics in the presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji, Jalore-Sirohi MP Shri Lumbaram Chaudhary, Jalore MLA and Chief Whip of Rajasthan Govt. Shri Jogeshwar Garg, and Jodhpur Anchal GS Shri Suresh Vishnoi on 9th May.

Shri Prakash Chandra Ji spoke on current global situation, shedding light on the changing economic environment, challenges of the global market, and the need for innovation in industries. He urged the entrepreneurs to work towards quality, technological upgradation, and self-reliance.

At this juncture, local entrepreneurs came forward enthusiastically for financial contribution for proposed Skill Development Center on the newly allotted 1021 square meter land in the RIICO industrial area. Shri Anil Chaudhary-Shri Ram Granite, Shri Ramesh Bohra-Shri Fateh Granite and Shri Ram Grani Marmo announced contributions of 11-11 lakh rupees each.

In addition, the Granite Association Jalore and Kanwala Cheema Pink Granite Mining Organization assured substantial financial contributions. Besides these, other entrepreneurs including Shri Banshidhar Chaudhary, Shrikanta Bhutada, Jethalia family, Shri Dinesh Goyal, Shri Mahesh Mor, Shri Ramniwas Chaudhary, Shri Chandan Singh Korana, Shri Ramratan Chaudhary, Shri Sohan Agarwal, Shri Bhavani Singh Dhandhiya, Shri Aman Agarwal, Shri Kamal Jakhar, Shri Gopal Swami, and others also announced contributions.

All members present in the meeting expressed gratitude for the Rail service initiated from Jalore to Delhi through the efforts of LUB. Jalore unit President Shri Dinesh Agarwal welcomed the guests, and Secretary Shri Krishna Kumar Jethalia expressed vote of thanks.

लघु उद्योग भारती उत्पाद समूह चिंतन-बैठक

विशेष रिपोर्ट
उद्योग टाइम्स डेस्क

लघु उद्योग भारती के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय पर उत्पाद समूह की दो दिवसीय (23–24 मई) चिंतन बैठक आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्पाद समूह के राष्ट्रीय समन्वयक श्री घनश्याम ओझा सहित 10 उत्पाद समूहों से जुड़े उद्यमी पदाधिकारियों की विशेष उपस्थिति रही।

सर्वप्रथम **राष्ट्रीय महामंत्री श्री ओमप्रकाश गुप्ता** ने अपने स्वागत कथन के बाद उत्पाद समूह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में कुल 14118 HSN Codes, 98 उत्पाद श्रेणियां और 7 करोड़ एमएसएमई हैं। संगठन 27 उत्पाद समूह को लेकर जिस विजन के साथ काम कर रहा है, उसे विविध उत्पाद से जुडी एसोसिएशन भी देख रही हैं।

श्री गुप्ता ने बताया कि दुनिया में तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है और उद्योग प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ही उत्पाद समूह की रचना की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि फार्मा, टेक्सटाइल और एग्रो–फूड उत्पाद समूह के कॉन्क्लेव दिल्ली में इसी वर्ष आयोजित किये जायेंगे।

उत्पाद समूह के राष्ट्रीय समन्वयक श्री घनश्याम ओझा ने बताया कि वैश्विक व्यापार परिदृश्य में प्रत्येक उत्पाद का 360 डिग्री पर विश्लेषण करने के लिए SOP तैयार की गई है जिसमें उत्पाद के रॉ मटेरियल, आयात–निर्यात, तुलनात्मक वैश्विक साझेदारी, तकनीक, स्किल्स, लेबर, गुणवत्ता, प्रोडक्ट कॉस्ट, सरकार की पॉलिसी, भविष्य के अवसर और चुनौतियां जैसे करीब 20 बिंदु हैं। हरेक प्रोडक्ट ग्रुप के लिए विजन डॉक्यूमेंट–2047 तैयार किया जा रहा है। श्री ओझा ने इसे युगांतकारी कदम बताया।

वस्त्र उत्पाद समूह से श्री महेश हुरकट, श्री कपिल गुप्ता एवं श्री पवन सिंघल ने प्रतिनिधित्व किया। फार्मा उत्पाद समूह से श्री राजेश गुप्ता, **प्लास्टिक उत्पाद समूह** से श्री वजुभाई वघासीया एवं श्री हितेन भेडा, हैंडीक्राफ्ट उत्पाद समूह से श्री सुरेश विश्नोई, **जेम्स एंड ज्वेलरी उत्पाद समूह** से श्री मनीष जौहरी, **इलेक्ट्रिकल उत्पाद समूह** से श्री आर. के. बंसल और

श्री प्रमोद मोर, **पैकेजिंग उत्पाद समूह** से श्री केपी सिंह और श्री विवेक अग्रवाल एवं **माइंस एंड मिनरल्स उत्पाद समूह** में श्री नरेश पारीक, श्री नटवर लाल अजमेरा एवं सीए योगेश गौतम ने भागीदारी की। उन्होंने बताया कि राजस्थान के मकराना में CNC मशीनों का प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जायेगा। साथ ही 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्टोनमार्ट प्रदर्शनी के लिए राजस्थान सरकार से एमओयू किया जाना सुनिश्चित है **फुटवियर उत्पाद समूह** से श्री सुनील चावला ने मैन मेड और मशीन मेड फुटवियर के उत्पादन के बारे में बताया। उन्होंने मादीपुर फुटवियर क्लस्टर से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की।

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद समूह से श्री मितेश लोकवाणी ने बताया कि कोरिया, ताइवान और चीन जैसे देशों पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक बाजार की निर्भरता बनी रहती है। यहां से सस्ते कॉम्पोनेन्ट मंगवा कर असेम्बल भी किया जाता है। कम कीमत में क़्वालिटी प्रोडक्ट निर्माण करना बड़ी चुनौती है।

इस अवसर पर **राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी** ने कहा कि भारतीयों में चमत्कारिक परिणाम देने की प्रवृत्ति सदियों से रही हैं। उन्होंने उद्यमियों का आह्वान किया कि वैश्विक प्रतियोगिता में कॉस्ट फैक्टर के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट पर भी काम करना होगा।

बड़े लोगों के साथ लड़ना, सरकार से लड़ने जैसा ही है। सरकार अनुकूल हो या प्रतिकूल, अनुचित दबावों में से रास्ता बनायें। चांदी के सिक्कों में बिकने वाले पहले भी थे, और आज भी हैं। संगठन में अच्छे लोगों का समूह दिखता है, तो लोगों के मन में भी उत्साह बनता है। वे हमारे कमिटमेंट को परखते हैं। नैतिक सामर्थ्य, संगठन का विस्तार, सरकार से सामंजस्य बनाते हुए आर्थिक समृद्धि की अतीत की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हमें निरंतर करना है। इस अवसर पर श्री आलोक सोंथलिया, श्री एम. शिवकुमार और श्री जितेंद्र चुग वर्चुअल प्लेटफार्म पर जुड़े। ❑ ❑ ❑

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ मिशन ज़ीरो टोलरेंस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर वज्र प्रहार

आरएएस सहित 20 को नौकरी से किया बर्खास्त, 332 निलंबित, 17 की पेंशन बंद की

चर्चा में

उद्योग टाइम्स डेस्क

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सुशासन और सुराज की स्थापना एवं प्रशासनिक तंत्र को जवाबदेह बनाने के लिए भ्रष्ट एवं अकर्मण्य अधिकारियों के खिलाफ बेहद सख्त और निर्णायक अभियान छेड़ा है। इस कार्यवाही से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी नौकरी जनसेवा के लिए है, न कि पद के दुरुपयोग, रिश्वतखोरी और मनमानी के लिए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी और कर्मचारी जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेंगे, विकास कार्यों में बाधा डालेंगे या अपने कर्तव्यों से विमुख होंगे, उनके लिए सरकार में कोई स्थान नहीं है।

मुख्यमंत्री के इस जन–हितैषी रवैये की प्रदेश ही नहीं, देश के राजनीतिक हलकों में जबरदस्त चर्चा है। राज्य सरकार द्वारा 577 प्रकरणों में जांच कर जिम्मेदारी तय की जा रही है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा के 9 प्रकरणों की जांच जारी है। प्रदेश में संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने बेझिझक रिश्वत, ट्रैप, पद का दुरूपयोग, आय से अधिक संपत्ति प्रकरणों के 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17–ए के तहत 37 अन्य प्रकरणों में भी कठोर कार्रवाई की है।

प्रदेश में पहली बार इतने स्पष्ट और कठोर शब्दों में यह चेतावनी दी गई है कि जनता को अनावश्यक चक्कर कटवाना, फाइलों को दबाकर रखना, सरकारी धन का दुरुपयोग करना और जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति अब किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगी। मुख्यमंत्री का संदेश साफ, सख्त और दो टूक है–जनता की सेवा करो, ईमानदारी से काम करो, अन्यथा सरकारी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहो।

लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री के फैसले और साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है जब

देश–दुनिया से यहां निवेश के जरिये उद्योग और रोजगार सृजन का प्रयास सरकार पूरी गंभीरता से कर रही है। उन्होंने बताया कि बीते बरसों में उद्यमी यहां निवेश के लिए आते, लेकिन विभागों के चक्कर काट कर थक जाते थे और बहुत से उद्यमियों के निवेश से प्रदेश अक्सर वंचित ही रह जाता।

मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) अधिकारी सहित 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि 332 अधिकारियों और कार्मिकों को निलंबित किया गया है। 17 कार्मिकों की पेंशन बंद की गई है तथा 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी कर भ्रष्टाचार के आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के 577 मामलों की जांच जारी है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि परिणाम देने वाली कार्रवाई कर रही है।

सेवानिवृत्ति बाद कार्रवाई से दिया सख्त संदेश–

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो अफसर जनता के पैसे पर डाका डालेगा, उसकी न नौकरी रहेगी, न पेंशन और न ही कानून से बचने का कोई रास्ता। सरकार ने 17 अधिकारियों को भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मामलों में आजीवन शत–प्रतिशत पेंशन एवं ग्रेच्युटी रोककर दंडित किया है। साथ ही भ्रष्ट अधिकारी की 3 वार्षिक वेतन वृद्धियां तक वापस ली गई हैं।

जांच के बाद दोषियों पर गिरेगी गाज–

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लापरवाह और अनुशासनहीन अफसरों पर कार्रवाई का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

❑ ❑ ❑

LUB's News in Brief

LUB's Puducherry EC meeting was conducted in the presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji. He highlighted the vital role of MSMEs in nation-building and urged members to adopt an 'Each one-bring one' policy to strengthen the organization. National Jt. GS Shri Mohana Sundaram. National EC member Shri Suresh Babu, State GS Shri Ashok and Shri Visweswaran were also present.

Tamil Nadu State EC meeting was conducted in the presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji at Erode on 28th May. During visit the Erode Women Cluster, the team displayed healthy food products manufactured with technology support of CSIR. On this occasion, state unit launched the two-day MSME Sangamam Expo scheduled on 30-31 July at Hosur. For this, a brochure was also released. The meeting was conducted by National Jt. GS Shri Mohanasundaram.

LUB's delegation led by Former National President Shri H.V.S. Krishna met Chief Minister Shri Yogi Adityanath regarding the proposed Defence Expo-2026 at Lucknow. On this occasion, UP State President Shri Ravindra Singh, Awadh Anchal GS Shri Arun Bhatia, Lucknow Unit President Shri Keshav Mathur, India Export Mart Ltd. Chairman Dr. Rakesh Kumar and CEO Shri Sudeep Sarkar were present.

Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai was invited to the IIF-India Industrial Fair, organized by LUB Chhattisgarh, which is scheduled to be held at Raipur from September 18 to 20, 2026. On this occasion, CM Shri Sai said that such events provide entrepreneurs from across the country with the opportunity to visit Chhattisgarh, thereby boosting investment in the state. He assured that the process of allocating land for LUB state office would be completed soon. State President Dr. (Smt.) Sipi Dubey, Secretary Shri Jitendra Chandrakar, Smt. Tulika Pandey, and Rasmada Unit President Shri Sanjay Mishra along with Secretary Shri Om Prakash Rajak were present on 22nd May.

LUB's delegation presented a memorandum to Shri Nand Gopal Gupta Cabinet Minister for Industrial

Development, Export Promotion NRI & Investment Promotion, Govt. of Uttar Pradesh regarding various problems in the industrial sector on 25th May. Shri Alok Jain-General Secretary, Shri Ayush Bansal-Treasurer, Shri Akshay Bansal and Shri Amitabh Nagarhia were present.

LUB's Assam state President Shri Partho Prateem has been nominated as a member of the State Level Selection Committee constituted by the Department of Industries, Commerce & Public Enterprise, Govt. of Assam, for the National MSME Awards-2024.

LUB & Telecom Sector Skill Council participated in an important strategic meeting regarding skill development in the electronics sector at Rail Bhawan, New Delhi on 25th May. The meeting featured detailed discussions on various programs, including promoting training in modern fields such as robotics, artificial intelligence, semiconductors, drones, and smart manufacturing. Positive consensus was reached on developing the Laghu Udyog Bharati Skill Center at Jaipur as a co-teaching center and training youth in Rajasthan.

During this time, Union Minister Shri Ashwini Vaishnaw's OSD Shri Mandar Deshpande, TSSC representative Lt. Col. Shri Sanjay Malhotra, ICEA representative Shri Rishabh Ahuja, LUB's former national Treasurer Shri Yogesh Gautam, National Jt. GS Shri Naresh Parikh, National Coordinator-Electronic Products Group Shri Mitesh Lokwani along with Shri Anil Gautam were present.

LUB's delegation led by Shri Bipan Syngal, President-West Bengal and CA Aditya Mitruka, President-North Bengal met Chief Minister-West Bengal Shri Suvendu Adhikari to discuss key industrial and economic issues concerning the region at Siliguri on 20th May. During the interaction, the delegation submitted a comprehensive strategic roadmap highlighting critical issues faced by MSMEs, including:

- Establishment of a regional single-window clearance mechanism
- Rationalization of industrial electricity tariffs
- Improved road and logistics connectivity
- Freight subsidy support for industries
- Leasehold to freehold land conversion reforms
- Tea industry revitalization and value-addition initiatives
- Creation of a secure and industry-friendly investment environment.

The memorandum also presented a district-wise export and product scaling matrix for West Bengal under the vision of decentralized industrial growth and global market integration. The Chief Minister assured that all proposals would be examined seriously for policy-level consideration.

LUB's delegation attended a crucial virtual meeting organized by the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, GoI. CA Mahesh Gupta National Treasurer, CA Nirmal Ojha National Jt. Treasurer, and CA Manoj Rungta State General

Secretary, Haryana represented the organisation. The delegation presented 4 critical demands to protect MSEs:

Dedicated Budget Sub-Quota: A strict, non-diversifiable fund allocation for Micro and Small units to prevent medium corporates from wiping out the corpus. Furthermore looking at high number of Micro and small industries, budgeting and monitoring should be implemented.

SMA-II Relaxation: Allow emergency credit access to SMA-II accounts, as these stressed units need immediate liquidity support the most.

Q3 & Q4 Peak Period: Calculate eligible loan amounts using the peak working capital utilization of both Q3 and Q4 (instead of just Q4) to capture seasonal credit needs fairly.

5-Day TAT & Auto-Approval: Mandate automated pre-approvals via banks' Core Banking Systems (CBS) and setup dedicated MSE helpdesks to ensure disbursement within 5 working days. The interaction was smooth and our suggestions were highly welcomed and officially noted for policy action by the DFS officials.

LUB's Agra unit organized a Foundation Day in the presence of Cabinet Minister for Tourism & Culture, UP Govt. Shri Jaiveer Singh; LUB's National President Shri Madhusudan Dadu; Chairman-UP Small Industries Corporation Shri Rakesh Garg, National Secretary Shri Deepak Agarwal; UP Jt. General Secretary Shri Gaurav Agarwal; Braj Anchal President Shri Rakesh Agarwal & General Secretary Shri Amalendu; Shahjahanpur Unit President; and Agra District President Shri Vijay Gupta on 24th May. General Secretary Shri Rajiv and CA Alok conducted the program.

The core committee meeting for EDP of South Sambhag, West Bengal was held on 16th May at Kolkata. South Sambhag President Shri K. K. Seksaria, National VP Shri Saroj K. Sahoo, EC Member-AIWC Shri Paul Mitra, LUB-SB Gen. Secretary Shri R.K. Sobhasaria, Asstt. Director MSME-DFO Shri Tapas Roy, GM-NCIC Dr. Anupam Gayen, Asstt. Director-KVIC Shri AP Chobin and Retired CGM-PNB Shri S. Agarwal were present.

Malwa Anchal meeting saw an enthusiastic participation from 33 out of the 41 units located across 16 districts at Ujjain on 16th May. The meeting reviewed

the membership expansion and notable activities carried out by the units over the past 4 months. National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji, Madhya Pradesh In-charge & National VP Shri Tara Chand Goyal. Former National President & MP regional In-charge Shri Vajubhai Bagasiya, State President Shri Rajesh Mishra and GS Shri Arun Soni, Malwa Anchal President Shri Rajendra Dubey & GS Smt. Seema Mishra were present.

LUB's delegation met Chief Minister, Uttrakhand Shri Pushkar Singh Dhami to discuss safety of employees and entrepreneurs working in industries, maintain law and order, and preserve the industrial environment in the SIDCUL on 15th May. On this occasion, Rajya Sabha MP Shri Naresh Bansal, Municipal Chairman-Shivalik Nagar, Haridwar Shri Rajiv Sharma, State GS Shri Rohit Bhatia, District President-Haridwar Shri Manoj Pundir, District EC Member Shri Bhola Singh and GM-Human Resources Siemens Shri Devendra Sharma were present.

LUB's National GS Shri Om Prakash Gupta, National Co-Convenor-Paper & Packaging Utpad Shri Vivek Agarwal met with Shri Harsh Malhotra-MoS-Corporate Affairs, Road Transport & Highways to present key concerns of the MSME sector on 13th May. LUB strongly recommended for an Amnesty Scheme under MCA giving a fair opportunity to genuine MSMEs to regularize their compliance status with minimum formalities and a small token amount of penalty. The delegation also urged for a clear and time-bound process for restoration of struck-off companies holding assets, ensuring that bona-fide businesses are allowed to operate with an opportunity to overcome procedural lapses.

A delegation led by National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji, along with National General Secretary Shri Om Prakash Gupta, National Jt. Gen. Secretary Shri Naresh Pareek, and National Co-Convenor-Paper & Packaging Samuh Shri Vivek Agarwal met Union Minister of Commerce & Industry Shri Piyush Goyal at New Delhi on 13th May.

The delegation raised key issues concerning MSEs exporters affected due to Iran war and restrictions being brought by USA on exports of Quartz Surface Slabs. Similarly, GST benefits available under NEIDS-2017 and Unnati-2024 to North-Eastern Region have been adversely affected due to recent changes in GST rates including need for a new policy framework and issue of recycling units were raised. To ensure availability of Skill workforce for footwear industry, request to establish a Skill Training Centre at Madipur Footwear Cluster and representation of MSMEs in the Export Promotion Council was made.

LUB's New Office at Siliguri (North Bengal) was inaugurated by National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji and MP-Darjeeling Shri Raju Bista on 24th May. Shri Prakash Chandra ji spoke about the Bengal Renaissance and how it can attain its lost glory and the pivotal role of Laghu Udyog Bharati to play in the current scenario. Special gratitude was expressed towards Shri Suresh Garg and Shri Prateek Garg of Tulsa Group for their selfless contribution in making the office establishment possible. On this occasion, National Vice President Shri Saroj K. Sahu; State In-charge Shri Praveen Agarwal, State President Shri Bipin Synghal, President-North Bengal CA Aditya Mitruka were present.

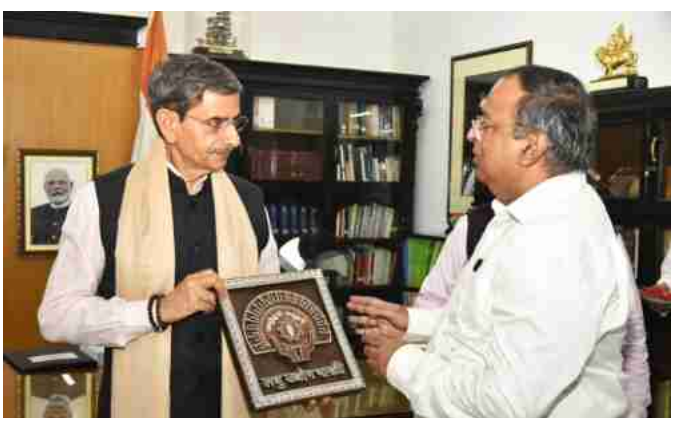

LUB's delegation met Governor-West Bengal Shri RN Ravi to discuss on the Roadmap for Entrepreneurship Development Program held at Lok Bhawan, Kolkata on 19th May. Shri Saroj K. Sahoo-National VP, Shri Paul Mitra EC Member-AIWC, Shri KK Seksaria President-South Sambhag, Shri Arunangshu Chowdhury & Shri Shuvam Banerjee Member, LUB along with senior officials of MSME DFO, NSIC & PNB were also accompanied as stake holders during the meeting. The Governor urged to start EDP with at least 100 entrepreneurs by end of 2026.

LUB's South Sambhag Office (West Bengal) was inaugurated in the presence of Mentor Shri Ashok Modi, who generously provided the office space. Along with National VP Shri Saroj K. Sahoo, AIWC Member Shri Paul K. Mitra, State GS Shri Deboprasad Mukherjee, South Sambhag President Shri K. K. Seksaria, GS Shri Ramesh Sovasaria and other office bearers were present at Kolkata on 12th May.

An important meeting regarding the proposed Defence Expo-2026 at Lucknow was held with Defence Minister Shri Rajnath Singh at New Delhi on 31st May. The delegation included LUB's former National President Shri H.V.S. Krishna, UP State President Shri Ravindra Singh, Awadh Anchal GS Shri Arun Bhatia, Lucknow Unit President Shri Keshav Mathur; Chairman-IEML Dr. Rakesh Kumar and CEO-IEML Shri Sudeep Sarcar.

In an important strategic meeting regarding skill development in the electronics sector between Laghu Udyog Bharti and Telecom Sector Skill Council held at Rail Bhawan, New Delhi, LUB's former National President and Coordinator- Utpad Samuh Shri Ghanshyam Ojha, former National Treasurer Shri (CA) Yogesh Gautam, National Jt. GS Shri Naresh Pareek and Shri Mitesh Lokwani joined.

Shri Rakesh Garg, Chairman-Uttar Pradesh Small Industries Corporation Limited, paid a courtesy call on Shri Bhupendra Singh, the newly appointed MSME Minister of the Uttar Pradesh govt. and held discussions regarding the development of the state's MSME sector at Lucknow.

The meeting of Chittor Anchal was held at Banswara in the presence of Rajasthan State President Shri Yogendra Sharma and RSS Banswara Vibhag Pracharak Shri Vikas Raj.

LUB's Alipurduar District Unit was Inaugurated in the presence of State In-charge Shri Saroj K. Sahu, West Bengal State President Shri Vipan Synghal and North Bengal President Shri Aditya Mitruka.

A workshop was organized under the aegis of the LUB's Jodhpur Mahanagar, Women's Wing and the Institute of Leadership Development to provide information on the new govt. schemes related to MSME-RAMP on 11th May.

LUB's Foundation Day Celebration

Team Spirit @ Goa State Unit

Entrepreneurship promoted @ Historical City Jhansi (UP)

Future Agenda Discussed @ Lucknow Unit

SIDCUL Haridwar & Roorkee Unit (Uttarakhand) jointly conducted

Hathras Unit of Uttar Pradesh

Nalagarh Unit of Himachal Pradesh

Baddi unit celebrated Foundation Day at Saraswati Vidya Mandir, Gullarwala

101 Progressive Women Entrepreneurs were honored at the 'Business Woman Excellence Award' organized by Rajkot Women's Wing.

LUB's Foundation Day Celebration

Harda District Unit of Madhya Pradesh

Barotiwala Unit of Himachal Pradesh

Parwanoo Unit of Himachal Pradesh

Chandrapur Unit of Maharashtra

Khandwa Unit of Madhya Pradesh

Hanumangarh Unit of Rajasthan

Himmat Nagar of Gujarat State

Sahibabad Unit of Ghaziabad District-UP

CPG
CHANDERPUR GROUP
(Since 1962)

Power your Industries, Furnaces, Hot Air Generators & any other applications where PNG / LPG or any other petrofuel is used any other petrofuel is used

Switch to CPG Biomass Gasifiers for reliable, efficient, and ecofriendly energy, keeping your operations running strong while cutting costs and emissions.

Save more with CPG Gasifier

5 kg wood pallets (@RS. 8/kg) will replace 1 kg LPG/PNG

Size Available : For Replacement of 8 liters per hr. to 240 liters per hr. ,petrofuel (approx.)

We also provide complete manufacturing solutions for

Cement Industries, Lime Industries, Mineral Processing Industries, Fertilizer Industries, Petro Chemical Industries,Flue Gas Desulfurization, Waste to Energy through Gasification, Paper Industries ,Defence, Aerospace, Nuclear and Batching Plants.

Jorian, Yamunanagar 135001, Haryana,India
F-5, Sec.-3, Noida 201301, Uttar Pradesh, India
+91 77985 00085
1800 121 6209
info@chanderpur.com
www.chanderpur.com

POLYPLASTICS
CREATING IDENTITIES

AUTOMOTIVE COMPONENTS MANUFACTURERS

WHEEL COVER GRILL LOGO EMBLEM

MANUFACTURING FACILITIES

• YAMUNANAGAR • BAWAL • BHIWADI • DASLANA • CHENNAI • KHARKHODA • PUNE • SANAND

Head Office:-
101, 1st Floor, Enkay Tower, Vanijay Nikunj, Phase 5, Gurugram, 122016

ADWIN®
SOLAR SOLUTIONS & APPLIANCES

Choose the BEST SOLAR SOLUTION

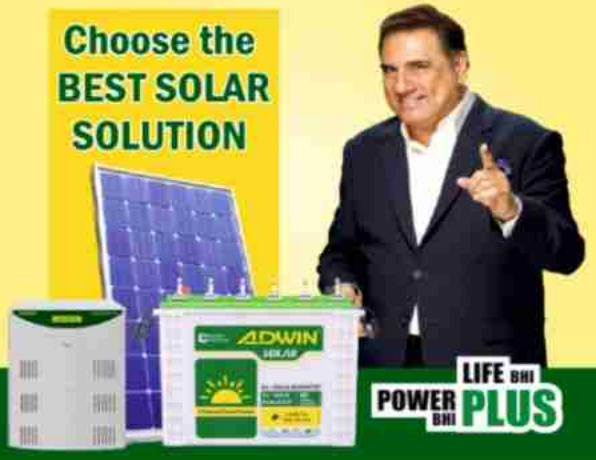

Our Range of Products :

BATTERIES & INVERTER | SOLAR PANELS | WATER HEATERS

CEILING FANS | LED LIGHTING

For Trade Enquiry call : 091389 - 53258
visit us : www.adwinpower.com
Follow us on

Oriental Engg. Works Pvt. Ltd.
OEW

Tangee
impulse
ROEMHELD
HILMA + STARK
Tractel

Engineering, Manufacturing, Installation, Maintenance and Sales services

- *Hydraulic equipment and systems*
- *Dewatering/ Fluid-transfer pumps*
- *Hydraulic work-holding solutions*
- *Building maintenance systems*

Breathing Life into your Concepts and Ideas

www.oewin.com Oriental Chowk, E-4A Industrial Area, Yamuna Nagar-135001 sales@oewin.com
+91-1732-251750 CIN #: U36492HR1938PT9923 GST #: 06AAACO8737D1ZI info@oewin.com

15th INDIA INDUSTRIAL FAIR UDYAM 2026

लघु उद्योग भारती
LAGHU UDYOG BHARATI
(GUJARAT)

15TH INDIA INDUSTRIAL FAIR 2026

THE LARGEST EXPO IN GUJARAT REGION

VENUE:
HELIPAD GROUND,
GANDHINAGAR, GUJARAT

DATES:
23TH TO 26TH OCTOBER 2026

WHY EXHIBIT?

- Excellent Networking & B2B Matchmaking Opportunities
- Direct Business & Investment Opportunities
- Technical Seminars, Workshops & Industry Conferences
- Product Launches & Live Technology Demonstrations
- Vendor Registration Support for Government Departments & PSUs
- Platform to Connect with Manufacturers, Dealers, Distributors & Buyers
- Opportunities for MSMEs, Start-ups and Industrial Suppliers to Expand Market Reach

Limited Stalls Book Early!

INVITING EXHIBITORS FOR STALL BOOKING

Be a part of one of India's leading industrial exhibitions and showcase your business to a national audience.

EVENT HIGHLIGHTS

- 400+ Exhibition Stalls
- 50,000+ Sq. Mtr. Exhibition Area
- 1,50,000+ Expected Visitors
- ₹1000 CRORES Business (Approx.)

For More Details

VAJUBHAI VAGHASIYA
+91 98243 00526

RAMESHBHAI THUMMAR
+91 98254 62308

DEVANGBHAI PATHAK
+91 98252 45610

STALL BOOKING
+91 88667 56788

EMPOWERING MSMES | DRIVING INNOVATION | CREATING OPPORTUNITIES

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

ग्राम 2026
ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट
23 - 25 मई 2026, जयपुर

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)

23-25 मई 2026 · जयपुर

नवाचार । खेती । उत्थान

GRAM 2026 कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हितधारकों के लिए एक आदर्श मंच होगा, जो एग्री-टेक (कृषि-तकनीक), प्रसंस्करण और मूल्य-वर्धित पारिस्थिति की प्रणालियों में अवसरों के द्वार खोलेगा

GRAM 2026 की मुख्य विशेषताएं

मेगा प्रदर्शनी	पैनल चर्चाएँ	ग्रामीण बाज़ार	स्टार्टअप कैंप
विषयगत सम्मेलन सत्र	स्मार्ट फार्मिंग शोकेस (आधुनिक खेती का प्रदर्शन)		B2B और B2G बैठकें

राजस्थान - निवेश के अवसर

कृषि-प्रसंस्करण	बागवानी	डेयरी और पशुपालन	सिंचाई तकनीक	कृषि यंत्रीकरण
पैकेज्ड फूड	जैविक खेती	कटाई के बाद की रसद	संरक्षित खेती	अनुबंध खेती

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

UDYOG TIMES | OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI | 30 May - 2026 | Registration No. RAJBIL/2016/69093
Postal Reg. No. : Jaipur City/433/2020-22

Follow us

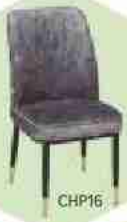

- lubindia
- lubindia
- @lubBharat
- lub.india
- laghu-udyog-bharati

LUB's Monthly Magazine Published by OP Mittal Printed at Raj Blocks, 22 Godown Ind. Area Kartapura, JAIPUR-302019